● वर्ष-4
● अंक-143
रायपुर, शनिवार
25 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

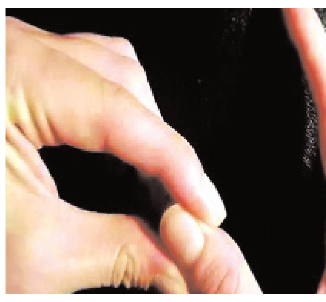

पेज-6» उंगलियों की ये 5 एक्सरसाइज आपको...

10 विपक्षी सांसद दिनभर के लिए समिति की सदस्यता से निलंबित

वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामा थमता न देख समिति के 10 सांसदों को पूरे दिन के लिए कमेटी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें मसौदा कानून में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। आज भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के विचार सुनने वाली थी।

बैठक में हुए हंगामे के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से सभी 10 विपक्षी सांसदों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद शामिल हैं।

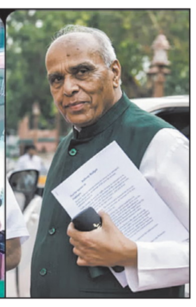

मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की और इसी दौरान विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में हंगामा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्द स्वीकार करने पर जोर दे रही है। बैठक के दौरान तीखी बहस के कारण कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। मीरवाइज के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल समिति की बैठक फिर से शुरू होने के बाद उसके सामने पेश हुआ।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बैठक से बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि समिति की कार्यवाही तमाशा बन गई है। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित संशोधनों पर खंडवार विचार करने के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि उनका आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ है और वे बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

समिति के समक्ष पेश होने से पहले मीरवाइज ने कहा कि वह वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं और धर्म के मामलों में सरकार के हस्तक्षेप नहीं करने का समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सुझावों को सुना जाएगा और उन पर अमल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए, जो मुसलमानों को बसहज महसूस कराए। यह पहली बार है, जब लगभग निष्क्रिय हो चुके अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद कश्मीर घाटी से बाहर कदम रखा है।

कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठक में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल चल रहा है। सभापति इस बैठक को आगे बढ़ा रहे हैं और वह किसी की नहीं सुन रहे हैं। हमें बताया गया था कि 24 और 25 जनवरी को बैठक होगी। अब आज की बैठक के लिए एजेंडे को खंड दर खंड चर्चा से बदल दिया गया है।

निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष के लोगों खासकर ओवैसी साहब की सोच है कि हमने जम्मू-कश्मीर का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं सुना और मीरवाइज उमर फारूक को बुलाया। उन्हें सुनने के लिए ही जेपीसी अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी और खंडवार चर्चा की। आज विपक्ष की सोच और नजरिया उजागर हो गया है। उन्होंने मीरवाइज के सामने हंगामा किया और बदसलूकी की।

निलंबित सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान हुए बवाल के बाद निलंबित विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर कई आरोप लगाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में विपक्षी सांसदों ने लिखा- %...जब आज सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई, तो हम विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की तरफ से कार्यवाही के संचालन के तरीके के खिलाफ अत्यंत सम्मान के साथ अपनी आवाज उठाई।

सांसदों ने आगे लिखा, %हमने नियमों में निर्धारित उचित प्रक्रिया की अनदेखी करके जेपीसी के एकतरफा और अनुचित तरीके से काम करने पर प्रकाश डाला। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 24 और

25 तारीख को बैठक के लिए पूर्व में दिए गए नोटिस के बाद से, हम सदस्यों ने 31 तारीख को संसद सत्र शुरू होने के कारण 27 से 30 तारीख तक निर्वाचन क्षेत्र/राज्यों में अपने कार्यक्रम तैयार किए और इस प्रकार 27वीं बैठक को स्थगित करने की प्रार्थना की। जबकि हमने इन उचित दावों को सभ्य तरीके से अध्यक्ष के सामने रखा, उन्होंने जवाब देने का प्रयास भी नहीं किया।

चूंकि हम सभी ने अपमानित महसूस किया, इसलिए हम खड़े हुए और अपनी मांगों को सुनने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। इस बीच, अध्यक्ष ने किसी से फोन पर बात की और अचानक और आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने चिल्लाते हुए हमारे निलंबन का आदेश दिया... हितधारकों की तरफ से उठाए गए इन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए जेपीसी की तरफ से एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में जेपीसी की कार्यवाही को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाना, छुपे हुए द्वेष से भरी एक पहेली के अलावा और कुछ नहीं है।पत्र में लिखा गया है कि, %हमारा मानना है कि जेपीसी के अध्यक्ष के पास समिति के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि जेपीसी के अध्यक्ष को कार्यवाही को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया जाए। अध्यक्ष को 27वीं बैठक स्थगित कर देनी चाहिए ताकि विपक्षी सदस्यों को नियमों और प्रक्रिया से हटकर अपनी दलीलें/दावे रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिल सके।

रायपुर। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रारंभ राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी , मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल जी सहित पदाधिकारी मौजूद।

हाथरस बिटिया प्रकरणः राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल

हाथरस। लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाथरस के एसीजेएम,एमपी एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ है। न्यायालय ने परिवादी के बयानों के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष के लिए कारण 12 दिसंबर 2024 को शांत एवं स्थिर गांव बूलगढ़ी का दौरा कर मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने को जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित एवं चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर अपने एक्स हेंडिल पर बयानबाजी की।

परिवाद में कहा गया कि न्यायालय के निर्णय 2 मार्च 2023 की एवं जानकारी होने के बावजूद भी बोले कि हाथरस बिटिया प्रकरण में पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने वीडियो एवं पोस्ट अपलोड की। परिवादी की ओर से राहुल गांधी को विधिक नोटिस भेजा गया था और अपने शेष जीवन को सुगम बनाने को प्रतिकर के रूप में 50 लख रुपए की मांग की थी। विधिक नोटिस के तामील होने के बावजूद जवाब भी नहीं भेजा। न्यायालय में परिवादी के बयानों के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।

प्रमुख समाचार

संगम में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक लगाई डुबकी

महाकुंभ नगर (प्रयागराज)। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि महाकुंभ मेला में जाने वाले सभी मार्गों पर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां चींटी की तरह रेंग रही हैं। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। मेला क्षेत्र के बाहर बनाए गए सभी पार्किंग में वाहनों को खड़ा कराया जा रहा है। जाम खुलवाने में पुलिस और ट्रैफिक के सिपाहियों के पसीने छूट जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को रात्रि 12 बजे तक 10 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। शुक्रवार को आंकड़ा 11 लाख के करीब पहुंच गया है। महाकुंभ में 12 दिनों में अब तक करीब 11 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

नहीं पेश हो सकी सीएजी रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 14 रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने में देरी पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट को आगे बढ़ाने में करीब 490 दिन की देरी की है। 13 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस देरी के लिए दिल्ली सरकार की तीखी आलोचना की थी। कोर्ट के समक्ष याचिका भाजपा विधायकों विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने दायर की थी।

विजयसाई रेड्डी ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा

नई दिल्ली। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगन रेड्डी के करीबी माने जाने वाले विजयसाई रेड्डी ने राजनीति छोड़ने और राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला किया है। विजयसाई रेड्डी वाईएसआरसीपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में रेड्डी ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। मैं कल 25 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होऊंगा। मैं किसी अन्य पद, लाभ की उम्मीद में इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं वाईएस परिवार का आभारी हूं, जिन्होंने चार दशकों और तीन पीढ़ियों तक मुझ पर विश्वास किया और मेरा समर्थन किया मुझे अवसर देने के लिए दो बार राज्यसभा सदस्य बनने और मुझे इतने ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए मैं जगन गारू को शुभकामनाएं देता हूं।संसदीय दल के नेता के रूप में राज्यसभा में फ्लोर लीडर के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, मैंने पार्टी और राज्य के हितों के लिए ईमानदारी से और अथक परिश्रम किया है। लगभग नौ वर्षों तक मुझे प्रोत्साहित करने, मुझे अपार शक्ति और साहस देने और तेलुगु राज्यों में मुझे पहचान दिलाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विशेष धन्यवाद।

योगी जी आपने बहुत सही बात कहीः केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को गाइड करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सड़कों पर खुलेआम गैंगवार हो रहे हैं। लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में हैं। केंद्रीय गृहमंत्री के पास दिल्ली के लिए वक्त ही नहीं है। दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बृहस्पतिवार को योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरी दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था बिल्कुल चरमा गई है। दिल्ली में 11 बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली को 11 हिस्सों में बांट लिया है और खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है।

एक्टिंग छोड़ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी

नईदिल्ली। 90 के दशक के दौरान बॉलीवुड में एक लोकप्रिय नाम रहीं ममता कुलकर्णी अब आधिकारिक तौर पर संन्यास लेने के बाद साध्वी बन गई हैं। वह महाकुंभ मेले में भी पहुंची हैं जहां उन्होंने किन्नर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। वह गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर भगवा बैग लटकाए नजर आईं। सोशल मीडिया पर ममता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक हिंदू साधु की तरह भगवा रंग की पोशाक पहने हुए देखी जा सकती हैं। पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम घाट पर अपना पिंड दान किया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि किन्नर अखाड़ा उन्हें महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यामाई ममता नंदगिरि रखा गया है। यह महादेव, महा काली का आदेश था। यह मेरे गुरु का आदेश था। उन्होंने यह दिन चुना। मैंने कुछ नहीं किया। बताया जा रहा है कि उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा। साध्वी बनने के बाद ममता ने कहा कि महाकुंभ में आना और आयोजन की भव्यता देखना उनके लिए बेहद यादगार पल है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे

विकसित भारत, महिला नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने का सफर जारी

अन्नपूर्णा देवी

जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के अपनी मंज़िल की तरफ आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव इस बात का प्रमाण है, कि हम महिलाओं के विकास से महिला-नेतृत्व में विकासतक के सफर में कितने आगे आ गए हैं। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था, च्ज्जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। किसी भी पंछी के लिए महज़ एक पंख के साथ उड़ना संभव नहीं है।ज्ज उनके इस कालजयी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की शुरूआत की। इस ऐतिहासिक पहल का मकसद भारत में गिरते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना था कि देश भर में लड़कियों और महिलाओं को वे सभी अवसर, देखभाल और सम्मान मिलें, जिनकी वे हकदार हैं।

2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 918 होने के साथ सामाजिक पूर्वाग्रहों और नैदानिक उपकरणों के दुरुपयोग की चिंताजनक तस्वीर सामने आई। एक लक्ष्य के साथ तथा जीवन-चक्र-केंद्रित कदमों के ज़रिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को न केवल इस तस्वीर को बदलने के लिए लॉन्च किया गया था, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव भी रखी गई, जहां महिलाएं नेतृत्व करें और आगे बढ़ें।

पिछले एक दशक में, इस योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, 2014-15 में जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। संस्थागत प्रसव के मामले भी 2014-15 में 61त्न से बढ़कर 2023-24 में 97.3त्न हो गए हैं, जबकि पहली तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण 61त्न से बढ़कर 80.5त्न हो गया है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51त्न से बढ़कर 2021-22 में 79.4त्न हो गया। इसके अलावा, पुरुष और स्त्री नवजात शिशुओं के बीच शिशु मृत्यु दर में अंतर तकरीबन खत्म हो गया है, जो उत्तरजीविता और देखभाल में समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, आंकड़ों में सुधार की सीमा से कहीं आगे निकल गया है।इसने महिला सशक्तिकरण के मायने ही बदलकर रख दिए हैं। अक्टूबर 2023 में 150 महिला बाइकर्स द्वारा 10,000 किलोमीटर की यात्रा, यशस्विनी बाइक अभियान जैसी पहल, भारत की बेटियों के अदम्य साहस का प्रतीक है। 2022 में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ने, स्कूल न जाने वाली करीब 1,00,786 लड़कियों को फिर से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, जो जीवन को बदलने में शिक्षा की शक्ति का प्रदर्शन है। कौशल विकास पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन ने, कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, जिससे हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अपने दृष्टिकोण के और करीब आ पाए।

आज, जब हम इस परिवर्तनकारी पहल के दस साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, साफ है कि मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अगर विकसित भारत के अपने सपने को हासिल करना है, तो यह तय करना जरूरी है कि लड़कियां और महिलाएं हमारे राष्ट्र-निर्माण प्रयासों के केंद्र में रहें। भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता, जब तक इस देश की लड़कियाँ और महिलाएँ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के काबिल नहीं हो जातीं। यह हमारे लिए निर्णायक कार्रवाई करने का वक्त है। हमें गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 के कार्यान्वयन को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा में ड्रॉपआउट दर को संबोधित करना चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए और लड़कियों के जीवन के हर चरण में ज़रुरी मदद देनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 41.7त्न थी। हालाँकि यह पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, लेकिन फिर भी यह पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी के मुकाबले कम है। ग़ौर करने की बात यह भी है कि शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी से कम है। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएँ अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्य में शामिल हैं। हमारा प्रयास न केवल अधिक महिलाओं के लिए अपने घरेलू क्षेत्रों को छोड़कर घर से बाहर रोजगार करने के लिए एक माहौल को बढ़ावा देना होना चाहिए, बल्कि एक वाजिब कैरियर और पेशे के तौर पर देखभाल कार्य को बढ़ावा देने के साधन भी बनाने चाहिए, ताकि जो महिलाएं देखभाल कार्य में प्रशिक्षित हैं, और इसे आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो वे इससे भी वित्तीय आज़ादी हासिल कर सकें और अपने प्रयासों से देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान भी दे सकें। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, कार्यबल लिंग में अंतर को कम करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20त्न की वृद्धि हो सकती है। भारत के लिए, यह सिर्फ एक अवसर नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए बेहद ज़रूरी है।

श्री सीमेंट की जांच रिपोर्ट आई सामने, कलेक्टर ने मांगा जवाब

■ एक के बाद एक 40 बच्चों की बिगड़ी थी तबीयत

बलौदाबाजार। श्री सीमेंट से निकलने वाली बदबूदार गैस के कारण खपराडीह स्कूल के विद्यार्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ने के मामले में अब सीमेंट कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कलेक्टर दीपक सोनी ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और तत्काल व्यवस्था सुधारने निर्देश दिया है।

बता दें, हाल ही में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के खपराडीह स्कूल में अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस मामले में श्री सिमेंट प्लांट पर आरोप लगे कि प्लांट के एएफआर से निकलने वाली बदबूदार गैस की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। घटना के दिन कलेक्टर-एसपी तत्काल अस्पताल में बच्चों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने घटना के बाद तत्काल जांच टीम बनाकर जांच करवाई, जिसमें श्री सीमेंट कंपनी की लापरवाही सामने आई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री सीमेंट को नोटिस जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, मामले में कलेक्टर के निर्देश के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहायक संचालक, हाईजिन लैब रायपुर, प्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलौदाबाजार, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, सहायक अभियंता, पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर एवं वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर ने 22 जनवरी 2025 को श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह की संयुक्त जांच की।

जांच में पाया गया कि श्री सीमेंट संयंत्र में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने कारखाने के अधिभोगी नीरज अखौरी और कारखाना प्रबंधक विजय अग्रवाल को तत्काल व्यवस्था सुधारने करने के निर्देश दिए और कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर आगे कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है।

मिली जानकारी अनुसार, जांच के दौरान सहायक संचालक, हाइजिन लैब के द्वारा कारखाने के नार्थ वेस्ट में स्थित एएफआर में मटेरियल व परिसंकटमय अपशिष्ट का भंडारण और लाईन-3 में रखा गया ए एफ आर मटेरियल का मल्टी गैस डिटेक्टर के माध्यम से हाईजिन लैब के द्वारा हानिकारक गैस का जांच किया गया। जांच में पाया गया कि क्षेत्र में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं है।

वहीं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने में जांच में पाया गया कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थापित ए एफ आर भंडारण कारखाने के लाईन 3 में स्थापित ए एफ आर भंडारण में परिसंकटमय अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। निकासी हेतु नियमानुसार नालियां व पिट का निर्माण नहीं किया जाना पाया गया। एसओपी और एमएसडीएस प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। श्रमिकों को कार्य अनुरूप सुरक्षा उपकरण प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 12, धारा 7 ए 2 (बी), 7 ए 2 (ए) और नियम 73 (1), नियम 127 एवं नियम 128 का उल्लंघन है।

क्षेत्रीय कार्यालय, छग पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा कारखाने की जांच में पाया गया, कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थापित ए एफ आर भंडारण कारखाने के लाईन 3 में स्थापित ए एफ आर भंडारण में परिसंकटमय अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में वाहनों के परिवहन के दौरान फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना पाया गया और हाऊस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाया गया। श्री सीमेंट संयंत्र में नियमों के पालन न किए जाने को लेकर सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने के एएफआर भंडारण क्षेत्र, एएफआर फीडर एवं एएफआर श्रेडर मशीन को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करते हुए सील कर दिया गया है।

देखना अब यह होगा कि क्या वाकई श्री सीमेंट की इस बड़ी लापरवाही पर जिला प्रशासन सहित राज्य शासन कड़ी कार्रवाई करता है, या केवल खानापूर्ति करता है।

जगदलपुर नगर निगम में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु

जगदलपुर। बस्तर संभाग के एकमात्र नगर निगम जगदलपुर में होने वाले चुनाव को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी- अपनी जीता का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर सिर्फ जनता को छला गया है।

कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाए कि बीजेपी के एक साल का कार्यकाल फेलियर है। जिसे लेकर जगदलपुर की जनता में आक्रोश है।1 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। शहर में गंदगी फैली हुई है। जगदलपुर शहर का सबसे बड़ा दलपत सागर गंदगियों से पट रहा है।

सुशील मौर्य ने कहा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। जगदलपुर के विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव शहर से बाहर रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता शहर के बीच का होगा। वो शहर के मुद्दों को लेकर प्रदेश में लड़ाई करके सुविधा उपलब्ध कराएगा।

वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। बीजेपी नेता संजय पाण्डेय के मुताबिक नगर निगम में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उससे पहले बीजेपी सरकार थी। जिसमें किरण देव और जितेश महापौर रहे। उस समय के विकास कार्यो को बर्बाद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने नगर निगम में किया है।

संजय पाण्डेय ने कहा इसके अलावा कोई नया काम नहीं किया है। इसीलिए बीजेपी सरकार बनने के बाद पुराने कामों का सौंदर्यीकरण करने के साथ नए कामों के तहत गंगामुण्डा, दलपत सागर, इंद्रावती नदी के साथ ही अन्य तालाबों के लिए भी उचित निर्णय लिया जायेगा। क्योंकि ये सभी जनता से जुड़ी और रोजगार से जुड़े कार्य है।

जगदलपुर नगर निगम इस बार सबकी नजरों में होगा क्योंकि स्थानीय विधायक और पूर्व महापौर किरण देव अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं।ऐसे में जगदलपुर नगर निगम बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है।वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने विकास कार्यों और किरण देव की अनुपस्थिति को ही मुद्दा बनाने का काम किया है।वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि जनता इस बार निगम सरकार में उन्हें मौका देगी,ताकि जो काम अधूरे रह गए हैं वो पूरे किए जा सके।

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में शव वाहन नहीं मिला, बयानबाजी हुई तेज

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 17 जनवरी को एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। बेटे की मौत के बाद एक पिता को उसका शव पिकअप गाड़ी में ले जाना पड़ा। इस मंजर को देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे। यह पूरा मामला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक श्यामबिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र का है।

मनेंद्रगढ़ जिला अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस के जिला महामंत्री राजकुमार केशरवानी ने इस घटना पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शव को ले जाने के लिए वाहन ना मिलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मनेंद्रगढ़ में इस तरह की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिनों पहले एक गर्भवती महिला को खाट में लेकर आया गया। स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है। मीडिया के जरिए ये मांग है कि स्वास्थ्य विभाग की मूलभूत सुविधाएं जरूर लोगों को मिले।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने कहा कि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। कांग्रेस कार्यकाल में अस्पताल से बच्चे को कुत्ता उठाकर ले जाता था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है इसलिए आरोप लगा रही है। शव वाहन नहीं मिलने की बात मंत्री तक पहुंचाई जाएगी और आगे ऐसी घटना ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा।

मनेंद्रगढ़ जिला अस्पताल के बीएमओ एसएस सिंह शव को पिकअप गाड़ी में ले जाने के मामले से अनजान नजर आए। उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने की बात बताई। बीएमओ ने कहा कि अस्पताल से किसी ने इस बात की सूचना उन्हें नहीं दी, साथ ही इस बात का आश्वासन दिया कि आगे पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की अव्यवस्था ना हो।

तेंदुआ का शिकार करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

सारंगढ़-बिलाईगढ़। वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शिकारी को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ तेंदुआ को जाल बिछाकर मारने का आरोप है। आरोपियों के पास से वन विभाग ने भारी मात्रा में बिजली और फैसिंग तार जब्त किया है।

जानकारी के मुताबिक, धनी गांव पैकिंग क्षेत्र के जंगल में 12 जनवरी को तेंदुआ का शिकार किया गया था। इसकी सूचना पर वन विभाग और डॉग टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। जिसके बाद मुखबीर और डॉग के संदेह पर टीम ने धनीगांव निवासी राम सिंह बरिहा और जय नारायण पटेल को हिरासत लिया गया। जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म कबूल किया। वन विभाग ने दिनों शिकारी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

रेंजर,सामान्य क्षेत्र, सेवक राम बैगा ने बताया कि अवैध शिकार के लिए तार बिछाया गया था, लेकिन उसमें तेंदुआ आकर फंस गया। इसकी जानकारी हमें अलगे दिन 12 जनवरी को मिली, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुआ के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच के लिए देहरादून सैंपल भेजे गए हैं। तत्पश्चात छानबीन किया और मुखबिर के जरिए दो शिकार को गिरफ्तार किया गया।

गणतंत्र दिवस पर पर्यावरण को बचाने का देंगे संदेश

खैरागढ़। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस बार खैरागढ़ में आयोजित परेड में जल संरक्षण और जैव विविधता पर आधारित विशेष झांकी प्रस्तुत की जाएगी। झांकी का थीम जल शक्ति अभियान पर केंद्रित है, जिसमें जिले की उपलब्धियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा।

खैरागढ़ जिले ने जल शक्ति अभियान के तहत 2 लाख 50 हजार घन मीटर पानी संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की है। इन प्रयासों के चलते जिले में जल स्तर में सुधार हुआ है। यह क्षेत्र अब जैव विविधता के लिए एक आदर्श स्थल बन गया है। पानी के संरक्षण ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित किया, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती दी है। पानी की उपलब्धता और पर्यावरणीय संतुलन में सुधार के परिणामस्वरूप खैरागढ़ की आद्र भूमि अब प्रवासी पक्षियों का बसेरा बन गई है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कॉमन पोशार्ड पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। ये पक्षी अपनी खूबसूरती और प्रवास के लिए मशहूर हैं। इनके आगमन से स्थानीय जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।

खैरागढ़ डीएफओ, आलोक तिवारी ने बताया, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली झांकी को कॉमन पोशार्ड पक्षी के आकार और स्वरूप के आधार पर डिजाइन किया गया है। झांकी में जल संरक्षण के महत्व और जैव विविधता को उभारा जाएगा। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। झांकी में नदियों, तालाबों और आद्र भूमि के चित्रण के साथ जल संरक्षण से होने वाले लाभों को भी दर्शाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के इस विशेष आयोजन से यह संदेश दिया जाएगा कि जल ही जीवन है और इसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। झांकी की यह पहल जिले को गौरवान्वित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी।

पूर्व जिला महामंत्री व पूर्व जनपद सदस्य पुष्पेंद्र भाजपा में शामिल

बालोद। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री व पूर्व जनपद सदस्य पुष्पेंद्र तिवारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए है। जिला प्रभारी शंकर अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने पुष्पेंद्र तिवारी को भाजपा का गमछा व माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया।

पुष्पेंद्र तिवारी कांग्रेस में 2001 से शामिल हुए थे। 2003 में ब्लॉक युवक कांग्रेस में अध्यक्ष रहे। 2005 में युवक कांग्रेस से विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के पांच साल प्रभारी मंत्री रहे। जनपद पंचायत के पूर्व सभापति भी रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर, देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री व प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में हो रहे कार्य से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए।

इस मौके पर वरिष्ठ नेता यशवंत जैन, प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णकांत पवार, अभिषेक शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन साहू, पूर्व विधायक प्रीतम साहू, वीरेंद्र साहू, पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश यादव, महामंत्री राकेश छोटू यादव, वरिष्ठ पार्षद कमलेश सोनी, मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी कमल पनपालिया, महामंत्री नरेंद्र सोनवानी, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष संजय साहू, विनोद जैन, समीर खान, नोहर साहू, बिरला मनहर आदि उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

समिति प्रबंधक और उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ एफआईआर

कोरबा। कोरबा में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले के 65 धान खरीदी केन्द्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में धान खरीदी केन्द्र उतरदा (विकासखंड पाली) और कुल्हरिया (विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा) के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। धान खरीदी केंद्र उतरदा में कुल 3684.00 क्विंटल धान (9210 बोरे) सत्यापन में कम पाया गया। 581 नए जूट बारदाने कम और 1195 पुराने बारदाने अधिक मिले। धान खरीदी केंद्र कुल्हरिया में 806.80 क्विंटल धान (2017 बोरे) कम पाया गया। इसके साथ ही कुल 8 धान स्टेक में से केवल 3 में ही सिंगल लेयर डनेज की व्यवस्था थी। इन गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने दोनों केंद्रों के नोडल अधिकारियों और सहकारिता विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही समिति प्रबंधकों और उपार्जन केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा को दिए हैं।

डॉक्टर के सपने को भाई ने किया पूरा

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के इंदिरा वार्ड में रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मरणोपरांत परिवार से अपने शव को मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को डोनेट करने की बात कही थी। जिसपर परिवार के लोगों ने इच्छा पूरी करने की बात भी कही थी। आठ वर्षों के बाद अचानक डॉक्टर के निधन से परिवार ने उनकी इच्छा के अनुसार शुक्रवार को उनके पार्थिव शरीर को मेकाज को सौप दिया गया। बताया जा रहा है कि इंदिरा वार्ड निवासी आयुर्वेदिक डॉक्टर चंद्रमोहन लाल गर्ग 72 वर्ष ने 10 जुलाई 2017 को अपने परिजनों से चर्चा के बाद शव मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाई के काम आने की बात कहते हुए शव को सौपने की बात अपने छोटे भाई मिथिलेश से कही, इस बात को लेकर परिजनों से चर्चा के बाद परिजनों ने इसकी सहमति दी और परिजनों ने मेडिकल कॉलेज डिमरापाल आकर सहमति से मृत्युपरांत शरीर दान करने की पत्र को भर कर दे दिया, 72 वर्षीय डॉक्टर चंद्र मोहन लाल गर्ग की गुरुवार की दोपहर को निधन हो गया था।

रुपये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर युवक से ठगी

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां रुपए इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर एक युवक से 5 लाख 21 हजार 655 रुपए की ठगी हुई है। मामला सिटी कोतवाली बेमेतरा क्षेत्र के ग्राम सेमरिया का है। पुलिस ने पीड़ित युवक दुर्गा सिंह पिता जगदीश राम चंद्राकर उम्र 37 के आवेदन पर तीन अलग-अलग मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ धारा आईटी की धारा 66डी-एलसीजी व 318(4)-बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। थाने से मिली जानकारी अनुसार आरोपी द्वारा तीन अलग-अलग मोबाइल नंबर से पीड़ित को व्हाट्सएप में मैक्स लाईफ एप भेजकर प्लेस्टोर से डाउनलोड कराया। इसमें रकम इन्वेस्ट करने पर रुपए बढ़ने की बात कही। इसी के झांसा में आकर युवक से 5 लाख 21 हजार 655रुपए ट्रांसफर करा लिया गया। ये ठगी 17 सितंबर 2024 से 17 अक्टूबर के बीच हुई है। इसके बाद पीड़ित को कोई फायदा नहीं हुई। पीड़ित द्वारा रुपए वापसी के लिए मांग किया गया। लेकिन, रुपए नहीं मिले।

सड़क किनारे खड़े ट्रक से बस की जोरदार टक्कर

महासमुंद। महासमुंद के सरायपाली में घंटेश्वरी मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, रोड किनारे खड़े ट्रक से यात्री बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्ची की मौत और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग से पुरी जा रही बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे में रोड किनारे ख़राब हालत में 2 दिन से ट्रक खड़ा था। बस में लगभग 43 लोग सवार थे, सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली लाया गया है। हादसे में 19 लोगो को गंभीर चोट आई है। प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

36 किलो कॉपर केबल चोरी के मामले में चालक गिरफ्तार

भिलाई नगर। औद्योगिक क्षेत्र हथखोज स्थित कंपनी से 36 किलो कॉपर केबल चोरी करने के मामले में भिलाई सेक्टर-6 निवासी चालक और खलासी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 305 के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रशासनिक प्रबंधक अनूप कुमार ने पुरानी भिलाई पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि 23 जनवरी को आरोपी कंपनी के अंदर कुमार ट्रांसपोर्ट की स्क्रैप गाड़ी क्रमांक सीजी 15 एसी 1175 लेकर आए थे। कंपनी के दक्षणी दिशा बाउंड्रीवॉल से बाहर कॉपर केबिल फेंका, जिसका वजन 36.800 किलोग्राम था जिसकी कीमत लगभग 22000 हजार रूपये है। गाड़ी चालक बी कार्तिक उर्फ अमनजीत निवासी सेक्टर-6 तेलगू पारा एवं राजकिशोर राम उर्फ रवि कुमार सेक्टर-6 तेलगू पारा भिलाई को केबल फेंकते हुए कंपनी के सुरक्षाकर्मी बसंत कुमार साहू और भोजकुमार कंवर ने देखा और पकड़ा।

रिहायशी इलाकों में घूम रही मादा बाघ, वीडियो बना रहे लोग

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पिछले कई दिनों से मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में मादा बाघ घूम रही है। मादा बाघ 4 मवेशियों का शिकार भी कर चुकी है। इलाके में बाघ के यहां वहां घूमने का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें कभी बाघ सड़क पर कभी बाउंड्री वॉल तो कभी रिहायशी इलाकों में घूमती नजर आ रही है।

गौरेला में बाघ के घूमने की सूचना वन विभाग आसपास के कई गांवों में फैला चुका है। बाघ को लेकर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग बाघ के आसपास जाकर उसका वीडियो बना रहे हैं। जो खतरे से कम नहीं है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का वन अमला लगातार बाघ के मूवमेंट पर नजर बना कर रखा है। लेकिन रिहायशी इलाके के ग्रामीणों में बाघ को लेकर काफी दहशत फैली हुई है।

दिसंबर 2024 के शुरुआत में मध्यप्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के मरवाही इलाके में बाघ घूमते हुए पहुंची। मरवाही वन मंडल से एमसीबी जिले के चिरमिरी पहुंचे बाघिन को कानन पेंडारी की रेस्क्यू टीम ने ट्रेंकुलाइज कर अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व एटीआर में छोड़ दिया था। जिसके बाद एटीआर से निकालकर बाघिन दोबारा मरवाही वन मंडल होते हुए कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में दाखिल हुई। वहां से धीरे-धीरे वापस मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र इलाके में बाघ घूमते हुए पहुंची।

मादा बाघ पिछले पांच दिनों से मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित अमरकंटक से लगे ज्वालेश्वर धाम मंदिर के नजदीक घूम रही है। बाघिन कभी मध्यप्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़ में घूम रही है। अमरकंटक और जलेश्वर पर्यटक क्षेत्र होने के कारण लगातार यहां पर्यटक और श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। जिसके चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया बाघिन का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

डीएफओ रौनक गोयल ने कहा बाघ की हर गतिविधियों में बराबर नजर बनी हुई है। साथ ही पड़ोसी प्रदेश मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों के भी संपर्क में है।

वन विभाग की टीम लगातार बाघ की निगरानी कर रही है। मरवाही वन मंडल के आसपास कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीणों को वन विभाग शासकीय भवन में शिफ्ट कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों का वन अमला लगातार बाघ के हर मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह रविवार को हुआ फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल

बिलासपुर। रविवार को पूरे देश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बिलासपुर में भी इसकी तैयारी की जा रही है और समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल पुलिस परेड मैदान में आज सवेरे संपन्न हुआ। सब कुछ ठीक उसी तरह व उसी क्रम से हुआ जैसे कि 26 जनवरी को इस स्थल पर होना है। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह इस अवसर पर मौजूद थे। अंतिम रिहर्सल को देखने बड़ी संख्या में शहर के नागरिक, छात्र - छात्राएं, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। रिहर्सल में अपर कलेक्टर आर ए कुरूवंशी मुख्य अतिथि की भूमिका में थे और स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर देशभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।

राज्य सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और वे सवेरे 9 बजे राष्ट्रध्वज फहराएंगे। श्री चौधरी यहां 11.30 बजे तक आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों में होंगे। इस बार 8 स्कूलों की टीमों को प्रस्तुति के लिए चयन किया गया है। आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। तेरह टुकडियों ने शानदार मार्च पास्ट कर अनुशासन का परिचय दिया। समारोह में छत्तीसगढ़ के विकास की झलक दिखाती विभागीय झांकी भी लोगों को देखने को मिलेगी।

बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि चौधरी नक्सल हिंसा में शहीद के परिवारों से मुलाकात कर उनके प्रति आदर और श्रद्धासुमन व्यक्त करेंगे। मुख्य समारोह का संचालन हमेशा की तरह व्याख्याता द्वय सौरभ सक्सेना और मुकुल शर्मा करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

अभिनंदन सिंह नियुक्त किए गए राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य

रायपुर। भारत सरकार ने राज्य विकास समन्वय व निगरानी समिति (राज्य स्तरीय दिशा समिति) में बिलासपुर निवासी अभिनंदन सिंह को सदस्य नियुक्त किया है। इस समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य स्तरीय दिशा समिति के पास केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के समन्वय और निगरानी का अधिकार होता है। इस उच्च स्तरीय समिति के राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष तो चीफ सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इनके साथ समिति में पक्ष-विपक्ष के चुने हुए सांसद, विधायक और सचिव स्तर के चयनित अधिकारी सदस्य होते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की जाने वाली सार्वजनिक निधियों के अधिकतम उपयोग के संदर्भ में व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय दिशा समितियों की परिकल्पना की है, जो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय और निगरानी करके योजनाओं का सुचारू रूप से पालन कर सकें। अभिनन्दन सिंह के पिता एसडी सिंह रिटायर्ड कर्मचारी और माता सीके सिंह रिटायर्ड प्रधान पाठिका हैं, और दो बहनें बंगलौर में मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्यरत हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लिए शुक्रवार को विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना के अनुसार षष्ठम् विधान सभा का पंचम सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक रहेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

चुनाव और आमजनों के हितों के लिए पटवारियों ने किया हड़ताल खत्म

रायपुर। लंबे समय से हड़ताल पर रहने वाले पटवारियों ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही आमजनों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हड़ताल को खत्म कर दिया है। पटवारी ऑनलाइन और नेट भत्ता की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्यों के खिलाफ हड़ताल पर 16 दिसंबर से हड़ताल पर थे। पटवारियों का कहना था कि जब तक ऑनलाइन कार्यों के लिए भत्ता नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा और हर सोमवार को काला कपड़ा और बाकी दिन काला फीता लगाकर काम कर रहे थे लेकिन ऑनलाइन कार्यों का विरोध जारी रखा था। यही कारण था कि काम भी प्रभावित हो रहा था लेकिन अब पटवारी पहले की तरह काम करेंगे। इससे आमजनों को होने वाली समस्या अब दूर हो जाएगी। राजस्व पटवारी संघ ने खुद हड़ताल को स्थगित कर दिया है।

मतदाता जागरूकता के लिए राज्यपाल डेका ने की अपील

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के प्रति अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों को लेकर सचेत रहें और अपने बहुमूल्य मत का उपयोग लोकतंत्र की मजबूती और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने के लिए करें। उन्होंने कहा कि एक सफल लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है, कि हर युवा भारतीय नागरिक स्वयं को मतदाता के रूप मे पंजीकृत कराए और समय-समय पर होने वाले निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग भी करें। श्री डेका ने कहा कि आज का दिन मतदाताओं की जागरूकता के लिए समर्पित है। हमारा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रजातंत्र को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए हमे धर्म, वर्ग, जाति समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुये बिना निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयरहित होकर मतदान करना चाहिए।

मंत्री राजवाड़े बलरामपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगी

रायपुर। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिला के पुलिस लाईन ग्राउंड में आयोजित 76वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। श्रीमती राजवाड़े कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगी और परेड की सलामी लेंगी। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े कार्यक्रम में देश के लिए शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगी। उनके द्वारा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य समारोह में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति होगी।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में फहरायेंगे राष्ट्रीय ध्वज

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल गुरुकुल खेल मैदान गौरेला में आयोजित 76वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंत्री श्री जायसवाल कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लेंगे। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। मंत्री श्री जायसवाल कार्यक्रम में देश के लिए शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे। उनके द्वारा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में प्रेक्षकों की बैठक आयोजित

चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

प्रेक्षकों को निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी हो: श्री अजय सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां नवा रायपुर, अटल नगर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में प्रदेश के नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के संचालन एवं प्रेक्षण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें प्रेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेक्षकों को उनके दायित्वों और अपेक्षाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रेक्षक का कर्तव्य है कि वह निर्वाचन प्रक्रिया के सभी चरणों में सजग और सतर्क रहें। श्री सिंह ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांति पूर्ण तरीके से आयोजित हों। उन्होंने कहा कि प्रेक्षकों को निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी होना चाहिए।

श्री अजय सिंह ने प्रेक्षकों को निर्देशित किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग ऑफिसर की आयोजित बैठक में आपको यथासंभव उपस्थित होना है परन्तु प्रेक्षकों को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और अधिकारियों की बैठक नहीं बुलानी है और न ही प्रेस द्वारा पूछने पर आपको कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। आयोग से आपको यदि किसी शिकायत पर प्रतिवेदन देने के लिए कहा जाए तो ऐसा तत्परता से करें और सीधे आयोग के सचिव को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने प्रेक्षकों से कहा कि चुनाव प्रक्रिया की सघन निगरानी, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना, मतदान केंद्रों पर व्यवस्था का जायजा लेना तथा किसी भी अनियमितता की तत्काल रिपोर्टिंग करना आदि जिम्मेदारी आपको दी गई है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।उन्होंने प्रेक्षकों से कहा, चुनाव लोकतंत्र की नींव है, और इसकी पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। मतदाताओं को स्वतंत्र वातावरण में अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर पर आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, सभी जिलों के लिए नियुक्त प्रेक्षक, आयोग की उप सचिव डॉ. नेहा कपूर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

परीक्षा को बनाये मन की इच्छा, परिणाम इच्छानुसार मिलेंगे: चोपड़ा

रायपुर। जैन संवेदना ट्रस्ट द्वारा बच्चों से बच्चों की बात कार्यशाला का आयोजन श्री आदिश्वर जैन माध्यमिक शाला , महावीर भवन में किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेन्द्र कोचर ने बताया कि बच्चों के मन में वार्षिक परीक्षा के डर को दूर करने व परीक्षा में सफलता के लक्ष्य निर्धारण हेतु मोटिवेशनल कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज की कार्यशाला में प्रसिद्ध शिक्षाविद विजय चोपड़ा ने मेरी परीक्षा मेरी तैयारी विषय पर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा कि परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए सही प्लानिंग , व्यवस्थित प्रिपरेशन व कड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। चोपड़ा ने अच्छे परिणाम के लिये प्लानिंग , प्रिपरेशन व परिश्रम को विस्तारित करते हुए कहा कि प्रिपरेशन के पूर्व अच्छी प्लानिंग करें।

कुल विषयों को परीक्षा के बचे दिन से भाग देकर प्रत्येक विषय के लिये दिन निर्धारित करें। प्रत्येक विषय को तीन श्रेणी में बांट लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न , मन पसंद सरल प्रश्न व कठिन प्रश्न। तैयारी करते समय सरल प्रश्न से आरम्भ कर आगे बढ़ेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कठिन प्रश्नों की तैयारी के लिए प्रातः काल का समय बेहतर होगा। इस तरह के प्रयास अच्छे परिणाम देंगे। परीक्षा की तैयारी को स्वयं की इच्छा बनाएं फिर सफलता सौ प्रतिशत तय है। परीक्षा को बोझ या हव्वा न मानें बल्कि परीक्षा पर हावी होकर तैयारी में जुट जाएं। लगन, मेहनत, अनुशासन व आत्मविश्वास से ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसे मूलमंत्र बनाएं , पूर्ण मनोभावों से किये परिश्रम से ही अच्छे परिणाम सामने आते हैं। अभी परीक्षा में एक माह का समय शेष है , एक बात तय है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नही होता सो विषयों के अनुसार टाईम टेबल सेट करें , ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करें अपनी क्षमता पर विश्वास करें व प्लानिंग से तैयारी आरम्भ कर देवें।

निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारी-कर्मचारी होंगे सम्मानित

रायपुर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विवेकानंद सभागार में 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे से राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।कार्यक्रम में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि रायगढ़ कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल को प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक 81.66 प्रतिशत मतदान कराए जाने, दुर्ग कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को शहरी क्षेत्र होने के बावजूद विगत लोकसभा चुनाव की तुलना में वर्ष 2024 में लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत में 2.48 प्रतिशत वृद्धि, दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी को धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हुए भी विगत लोकसभा निर्वाचन की तुलना में लोकसभा निर्वाचन 2024 में 10.39 प्रतिशत वृद्धि के लिए उत्कृष्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह को लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्य उत्कृष्ट तरीके से संपन्न कराने, राजनांदगांव जिले की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह को गुणवत्ता पूर्ण स्वीप गतिविधियां आयोजित करने और मुंगेली जिले के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पांडे को प्रवासी मजदूरों को मतदान के लिए प्रेरित करने संबंधी स्वीप गतिविधियों के लिए स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

चांदी में भी हालमार्क अनिवार्य करे केन्द्र सरकार: कमल सोनी

रायपुर। केन्द्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया जाना है, ऐसे में व्यापारिक संगठन अपनी ओर से सुझाव दे रहे हैं ताकि व्यापारिक हित में सार्थक निर्णय लिया जा सके। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जिनके पदाधिकारियों ने अपने पद संभालने के बाद से लगातार सराफा कारोबारियों के पक्ष में आवाज बुलंद की है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी व महासचिव प्रकाश गोलछा ने अपनी ओर से कुछ सुझाव प्रेषित किए हैं हमने एक राष्ट्र एक दर का सुझाव दिया है। इसी के साथ सोने की तरह चांदी में भी हालमार्क अनिवार्य किये जाने की मांग की है। सोने व चांदी पर जो आयात शुल्क छह फीसदी है उसे घटाकर चार फीसदी किया जाना चाहिए।

निगम चुनाव के लिए नाम तय करने में छूट रहा पसीना, मचा घमासान

रायपुर। राजधानी रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए 70 वार्डों में प्रत्याशियों का नाम तय करने में कांग्रेस को पसीना छूट रहा है। दावेदारों की भरमार है और हर कोई बांहे तानकर खड़े हो गए हैं,यहां तक ताल ठोक रहे हैं कि यदि नहीं मिली तो बागी होकर लड़ेंगे। अगले पांच साल को कौन देखा है? ऐसे में समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। बड़े नाम जिनका वार्ड आरक्षण से प्रभावित हो चुका है ऐसे लोग सुरक्षित वार्ड से आवेदन लगा दिए हैं। इनमें महापौर ढेबर का ही नाम सामने आ रहा है, भगवतीचरण शुक्ल वार्ड से उनका नाम गया है।

जबकि वर्तमान स्थिति में सभापति प्रमोद दुबे यहां से पार्षद हैं और उनकी दावेदारी पहले बनती है,उन्होने अपने वार्ड में पिछले कार्यकाल के दौरान काम भी बहुत कराया है जिससे उनकी जीत भी पक्की मानी जा रही है। ऐसे में क्या दुबे किसी और वार्ड से लड़ेंगे या अड़ जायेंगे? एक संभावना ये भी जतायी जा रही है कि महापौर के लिए दावा कर रहीं श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे का नाम फाइनल हो रहा है। तभी दुबे मैदान छोड़ सकते हैं। कुछ एक वार्डों में घमासान मच गया है,सदर इलाके के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ने दो

पूर्व पार्षदों को लेकर नामजद शिकायत कर दी है कि उन्होने पिछली बार पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया था। यदि उन्हे टिकट फिर से दी जाती है तो हार का जिम्मा लेने पार्टी तैयार रहे।

वहीं देवेन्द्रनगर इलाके से एक सक्रिय पार्षद का नाम पैनल से गायब होने की खबर से समर्थकों में भारी नाराजगी है। उन्होने दो टूक कर दिया है चुनाव तो लड़ेंगे चाहे पार्टी फाइनल करे या न करे। कल प्रभारी पायलट आ रहे हैं तब शायद नामों पर मुहर लगे. लेकिन जिला और पीसीसी के रिकमंड को ही वे मानेंगे क्योंकि उन्हे इतने नीचे स्तर के चुनाव के बारे कितनी जानकारी होगी। इन हालातों को देखकर लग रहा है कि कब्ड्डी नहीं खो-खो की तैयारी है।

परिवार, समाज और देश की शान, मान और अभिमान है बेटियां: साय

रायपुर। समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी बेटियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने हर परिवार की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सीएम साय ने कहा कि बालिकाएं देश-प्रदेश, समाज और परिवार की शान, मान और अभिमान होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सहज माहौल देने की जरूरत है। इसके लिए समाज को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है।

विष्णुदेव साय ने कहा छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की परंपरा रही है। इसी कारण प्रदेश की प्रगति में छत्तीसगढ़ की बेटियां अपना योगदान दे रही हैं। यह बहन बेटियों और माताओं के लिए बेहतर वातावरण से संभव हुआ है। साय ने कहा बेटियां खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें और घर परिवार के साथ देश-प्रदेश की उन्नति में भी सहभागी बने।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री ने सभी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण और नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। राजवाड़े ने कहा कि परिवार और समाज को भी बेटियों के साथ मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी बेटियों से कहा कि वे आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें, राज्य सरकार का सहयोग हमेशा उनके साथ है।

राम वन पथ गमन योजना के निर्माण कार्यों की होगी जांच

अजय चंद्राकर करेंगे सात सदस्यीय समिति की अगुवाई

रायपुर। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप पर साय सरकार जांच समिति का गठन किया है। सात सदस्यीय समिति की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्?ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर करेंगे।

बता दें कि विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान यह विषय प्रश्?नकाल के दौरान उठा था। विधायक अजय चंद्राकर ने राम वन गमन पथ में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए योजना में चंद्रखुरी और चंपारण को जोड़ने पर भी आपत्ति की थी। चंद्राकर ने कहा कि इन दोनों स?थानों पर भगवान राम गए ही नहीं तो इन?हें क?यों राम वन गमन पथ में जोड़ा गया। विषय पर विधानसभा में लंबी बहस के बाद मंत्री ने सोशल ऑडिट कराने की घोषणा की थी।

इस घोषणा के बाद अब जाकर सरकार ने जांच समिति का गठन किया है। अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में बनी समिति में अकलतरा विधायक राधवेंद्र कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। वरिष्ठ इतिहासकार प्रो। डॉ। एलएस निगम, पुरातत?व संचालनालय के उप संचालक पीसी पारख, पुरातत्ववेता प्रभात कुमार, जल संसाधन विभाग के एसके टीकम और शशांक सिंह को सदस्य बनाया गया है।

रायपुर नगरीय निकाय चुनाव: पत्नी के लिए टिकट जुगाड़ने में लगे नेता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। निकायों में आरक्षण के बाद अब पार्षद और मेयर के पद को लेकर उठापठक का दौर शुरु हो चुका है।आरक्षण को लेकर जिन दिग्गजों के वार्डों में बदलाव हुआ है,वो अब दूसरे वार्ड में अपनी जगह तलाश रहे हैं,वहीं जिन निकायों में मेयर की सीट महिला हुई है वहां पर दिग्गज अपनी पत्नियों को टिकट दिलाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं।हालात ये हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली दरबार तक नेता चहेतों का नाम लिस्ट की सूची में डलवाने के लिए पसीना बहा रहे हैं।

रायपुर नगर निगम में इस बार महिला प्रत्याशी को मेयर बनने का मौका मिलेगा।इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी-अपनी पत्नियों का चेहरा अपने नाम पर आगे रखना चाहते हैं।पत्नी के लिए नेता आलाकमान के दर पर फील्डिंग करने में व्यस्त हैं। पत्नी के मामले में टिकट लेने की बात करें तो इसमें सबसे आगे कांग्रेस दिखाई दे रही है।

कांग्रेस के ज्यादातर दावेदार महिला किसी ने किसी बड़े नेता की पत्नी है। इनमें दीप्ति दुबे निवृत्तमान सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी,अरजुमन ढेबर निवृत्तमान महापौर एजाज ढेबर की पत्नी, परमजीत जुनेजा पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा की पत्नी सहित कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने महापौर पद के लिए कांग्रेस से दावेदारी की है। वहीं बीजेपी में अब तक किसी भी महिला दावेदार का नाम सामने नहीं आया है।

इस पूरे मामले में जब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की पत्नी ने टिकट मांगे हैं। जो इस ओर इशारा करता है कि पार्टी में महिला नेत्रियों का अभाव है। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस ने महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया है। यही वजह है कि वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है।

संजय श्रीवास्तव ने कहा जो नेता बेरोजगार हैं वो अपनी पत्नियों के सहारे अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं।जहां कैंडिडेट नहीं है वहां यदि पत्नियों को टिकट दिया जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ पत्नियों को ही टिकट दिया जाए तो बाकी की पार्टी की दूसरी महिला नेत्री कहां जाएंगी।

वहीं बीजेपी में पत्नियों को टिकट दिए जाने के सवाल पर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी में चयन का आधार अलग है।मंडल से लेकर जिले, संभाग में जो दावेदारी करते हैं, उसका पैनल बनाया जाता है। संभाग स्तर फाइनल होता है। अलग-अलग कैटेगरी की समिति है। वो इसे फाइनल करती है। यहां पर सिस्टम बना हुआ है, जो पार्टी के मापदंड और सिस्टम पर खरा उतरेगी ,वहीं उम्मीदवार बनेगी।

वहीं बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकता है। उन्हें अधिकार दिया गया है। बीजेपी के नेताओं को दावेदारी करने का अधिकार नहीं है। लिफाफा संस्कृति बीजेपी की है। वहां ऊपर से लिफाफा में नाम आता है।जिसे खोलकर बता दिया जाता है। सुरेंद्र वर्मा ने कहा ये जरुरी नहीं कि जनप्रतिनिधियों की पत्नी को ही टिकट दिया जाए। जो भी दावेदार हैं वो अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और किसी ना किसी रूप में पार्टी और संगठन में सक्रिय होते हैं। बड़े नेता के साथ उनके परिजन भी पार्टी में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। वह सामाजिक फिगर है। लेकिन टिकट का पहला अधिकार कार्यकर्ता का है। सभी सदस्यों के नाम पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है।

वहीं पत्नियों को टिकट देने के मामले में वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि इस तरह के दावेदार कांग्रेस में ज्यादा है। बड़े नेताओं से जुड़े लोगों को टिकट देना इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि आजकल चुनाव काफी खर्चीला हो गया है। ऐसे में सामान्य नेत्री या महिला कार्यकर्ता के लिए पहला चुनाव लड़ना काफी कठिन होगा। जिस वजह से भी पार्टी बड़े नेताओं की पत्नियों को टिकट दे सकती है।

उचित शर्मा ने कहा पार्टी के बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि यदि आरक्षण की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ सकते तो क्यों ना उनकी जगह से उनकी पत्नी दावा करें और चुनाव लड़ें। लेकिन इस तरह की व्यवस्था ज्यादातर कांग्रेस में ही देखने को मिल रही है।

वहीं टिकट देने को लेकर उचित शर्मा ने कहा कि यदि बड़े नेताओं की पत्नियों को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं दशकों से पार्टी का झंडा उठाए महिला कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। क्योंकि वो इतने साल ईमानदारी से इसी दिन का इंतजार करते हैं।लेकिन आगे चलकर उनकी सुनवाई भी नहीं होती।इसलिए आजकल टिकट वरिष्ठ की जगह घनिष्ठ को ही मिलता है।

पत्नियों को टिकट देने को लेकर सभी की अलग-अलग राय है।लेकिन किसी नेता की पत्नी को यदि टिकट मिलता है तो वो महिला दावेदार जो उस टिकट का हकदार थी, उन सभी की उम्मीदों पर पानी फिरता है।पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसी स्थिति में मान मनौव्वल करके कार्यकर्ताओं को मना लेते हैं।लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता।कई बार इस चीज को अपमान मानकर कार्यकर्ता पार्टी के विपरीत काम करने लगते हैं,जिससे पत्नी पर खेला गया दाव उलटा भी पड़ जाता है।फिलहाल रायपुर में यदि किसी बड़े नेता की पत्नी को टिकट देने की फैसला कोई भी पार्टी करती है तो सबसे पहले उन महिला कार्यकर्ताओं को साधना होगा,जिनके बूते महिला ब्रिगेड मौजूदा समय में खड़ी है।

दिल्ली में मुफ्त चुनावी उपहारों के शोर में असल मुद्दे दब गये

नीरज कुमार दुबे

अक्सर आपने देखा होगा कि किसी राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक और सामाजिक समीकरण हावी हो जाते हैं लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हालात एकदम अलग हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक चर्चा में ''मुफ्त उपहारों'' की चर्चा हावी है जिससे प्रदूषण, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बुनियादी ढांचा सहित अन्य प्रमुख मुद्दे पीछे रह गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के लिए निश्शुल्क सार्वजनिक परिवहन पहल पर जोर देते हुए ''रेवड़ी पर चर्चा'' जैसे अभियानों का नेतृत्व कर रही है। इसने नयी योजनाओं की भी घोषणा की है, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने के वादे के साथ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संजीवनी योजना शामिल है। कांग्रेस ने जवाब में 'प्यारी दीदी योजना' की घोषणा की है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही गई है। इसने 25 लाख रुपये तक की बीमा कवरेज का वादा करते हुए 'जीवन रक्षा योजना' की घोषणा भी की है। वहीं भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र के दो चरण अब तक जारी किये हैं जिनमें हर वर्ग के लिए योजनाओं की भरमार है। देखा जाये तो इन मुफ्त योजनाओं को एक बार 'मुफ्त की रेवड़ी' करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना पड़ा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो इस तरह की योजनाएं जारी रखी जाएंगी। इस बीच, मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाओं के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा गौण हो गया है। हालांकि राजधानी के ज्यादातर निवासियों ने गंभीर स्वास्थ्य खतरा बने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कार्य योजनाओं की कमी पर चिंता जताई है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले साल नवंबर में 490 के अंक को पार कर गया, जो ''अत्यंत गंभीर'' श्रेणी में आता है। जहरीली हवा के कारण अनेक लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण पूरे शहर में पानी की कमी भी देखी गई क्योंकि जलशोधन संयंत्र पानी का शोधन करने में असमर्थ थे। यही नहीं, खराब जल निकासी के चलते दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबने से मौत को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में आक्रोश देखा गया था। बहरहाल, देखा जाये तो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से शासन एवं नीति-निर्माण पंगु हो गये हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोजगार सृजन और संविदा कर्मचारियों के लिए समाधान खोजने जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों की अनदेखी की है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त योजनाओं की जो आदत जनता को लगाई है उसको देखते हुए अन्य पार्टियां भी इसी नीति पर चलती नजर आ रही हैं। यह नीति राजनीतिक दलों को सत्ता तो दिला देगी लेकिन सरकारी खजाने को और राज्य की आर्थिक सेहत को खासा नुकसान पहुँचाएगी। यहां सवाल यह भी उठता है कि हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन जब देश की राजधानी ही विकसित नहीं होगी तो यह लक्ष्य आखिर कैसे हासिल होगा?

अप्रवासियों के लिए ट्रंप का आना

रितिका

न्यू जर्सी में रहने वालीं प्रीति बहुत डरी हुई हैं। उन्होंने सुना है कि पुलिस और इमिग्रेशन विभाग के अधिकारी घर-घर जाकर विदेशियों की पूछताछ कर रहे हैं। डीडब्ल्यू हिंदी से बातचीत में उन्होंने बताया, डर लगा रहता है कि कोई अभी आकर बोल देगा कि अब हमें अमेरिका से जाना होगा। प्रीति जैसे डर में इस वक्त अमेरिका के लाखों लोग जी रहे हैं। यह डर तभी से शुरू हो गया था जब नवंबर में डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। भारतीय विदेश मंत्री एस। जयशंकर और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी रूबियो ने आप्रवासन का मुद्दा उठाया है।

20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डॉनल्ड ट्रंप ने कई आदेश जारी किए। इनमें से ज्यादातर आदेश वही हैं, जिन्हें पूरा करने के वादे ट्रंप ने किए थे। उनके कार्यकारी आदेशों में सबसे ऊपर है, आप्रवासन से जुड़े आदेश। इसमें आप्रवासन के लिए बनाए गए ऐप सीबीपी को बंद करना, जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को रद्द करना, सीमा पर आपातकाल लगाना, जरूरत पड़ने पर सेना को सीमा पर भेजना जैसे फैसले शामिल हैं। शपथग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों के लिए क्रिमिनल एलियन शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके चुनावी प्रचार के वादों में ही यह साफ झलक गया था कि उनका आने वाला कार्यकाल आप्रवासियों के लिए बेहद कठिन होने वाला है। खासकर उनके लिए जो अमेरिका आना चाहते हैं।

सैन डिएगो से सटी सीमा पर मेक्सिको की मारिया मारकाडो अपना फोन देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। आखिरकार उन्होंने फोन चेक किया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चार घंटे बाद मारिया की अपॉइंटमेंट, अमेरिका में कानूनी तौर पर प्रवेश करने की थी, लेकिन सीबीपी ऐप का नोटिफिकेशन बता रहा है कि आप्रवासियों की सारी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई हैं। मारिया के आस पास मौजूद दूसरे आप्रवासी भी एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे या निराश थे। इनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अब उनके पास क्या विकल्प बचे हैं। इस ऐप के बंद होते ही अमेरिका जाने की उनकी सारी उम्मीदें फिलहाल खत्म होती दिख रही हैं।

दरअसल, ट्रंप के शपथ लेने के कुछ घंटों के अंदर ही आप्रवासियों के लिए बनाए गए कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऐप ने काम करना बंद कर दिया। इस ऐप का मकसद था अमेरिकी सीमाओं पर अवैध आप्रवासियों के प्रवेश को रोकना। ऐप के जरिए आप्रवासी अमेरिकी प्रशासन के साथ अपॉइंटमेंट लेते थे ताकि वे वैध तरीके से अमेरिका आ सकें। इसके तहत उन्हें दो साल तक का वर्क परमिट मिलता था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक महज 1,450 स्लॉट्स के लिए करीब 2,80,000 लोग लॉग इन करते थे। महीनों के लंबे इंतजार के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलती थी।

ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक अब ना सिर्फ इस ऐप के जरिए अपॉइमेंट मिलनी बंद हो गई है बल्कि जिन्हें पहले से अपॉइंटमेंट मिली हुई थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया। ऐप पर यह नोटिफिकेशन आते ही अमेरिकी सीमाओं पर हताश आप्रवासियों की भीड़ दिखी।

यह ऐप मेक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया जैसे देशों के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 लाख आप्रवासियों ने इस ऐप के जरिये दो सालों में अपॉइंटमेंट ली। साथ ही इस ऐप की मदद से अवैध तरीके से अमेरिका आने वाले आप्रवासियों की संख्या में भी कमी देखी गई।

अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के डिप्टी चीफ मैथ्यू हूडाक के मुताबिक अब जब यह ऐप बंद हो गया है तो शायद सीमाओं पर अब लोग अवैध तरीके से घुसने की ज्यादा कोशिश करेंगे। इस ऐप का बंद होना आप्रवासन पर ट्रंप के सबसे कठोर फैसलों में से एक है।

ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक अब अमेरिका में अवैध तरीकों से रह रहे आप्रवासियों और अस्थायी तौर पर रह रहे आप्रवासियों के जो बच्चे अब वहां पैदा होंगे, उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। आदेश जारी करने से पहले ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही इकलौता देश है जहां ऐसा प्रावधान है और ये बिलकुल बेतुका है।

अमेरिकी कानून के मुताबिक वहां पैदा होने वाले बच्चों को अपने आप ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं। अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के तहत यह अधिकार दिया गया है। इसलिए ट्रंप के इस आदेश को कानूनी बाधाओं से भी गुजरना पड़ सकता है।

ट्रंप के इस आदेश के बाद लगभग 24 डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों और शहरों ने उनके खिलाफ संविधान की अवहेलना का मामला दर्ज करवाया है।मानवाधिकार और आप्रवासियों के लिए बने संगठन उनके इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी भी करने लगे हैं। ट्रंप के आदेश के तुरंत बाद ही अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इस फैसले के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। फैसले को असंवैधानिक बताते हुए यूनियन के वकील एंथनी रोमेरो ने कहा कि ये ना सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि यह अमेरिकी मूल्यों को लापरवाही और निर्ममता के साथ नकारना है।

अपने पहले कार्यकाल के दौरान डॉनल्ड ट्रंप ने अवैध आप्रवासन पर रोक लगाने के लिए अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का आदेश जारी किया था। तब यह ट्रंप वॉल के नाम से जाना गया। ट्रंप के नए कार्यकारी आदेशों की फेहरिस्त में अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाने को पूरा समर्थन देना भी शामिल है। खासकर मेक्सिको और अमेरिकी की सीमा से आने वाले आप्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन की खास नजर होगी।

पहले कार्यकाल में ही ट्रंप ने रिमेन इन मेक्सिको नाम की नीति शुरू की थी जिसके तहत अमेरिका में आने वाले शरणार्थियों को मेक्सिको में ही इंतजार करना पड़ता था। हजारों की तादाद में लोग कैंपों में अपनी बारी का इंतजार करते। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंपों में लोगों के साथ बलात्कार, अपहरण और लूटपाट जैसी घटनाएं भी हुईं। बाइडेन प्रशासन ने इस नीति को अमानवीय बताते हुए हटा दिया था। अब ट्रंप का दावा है कि वह फिर से इस नीति को लागू करेंगे। मौजूदा अमेरिकी सरकार के वादों में वहां पहले से ही रह रहे अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने की योजना भी शामिल है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 तक अमेरिका में एक करोड़ से अधिक लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिकी सीमा में प्रवेश किया है इसलिए बड़ी संख्या में उन लोगों को वापस भेजना भी जरूरी है। हालांकि, ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि ऐसा करना अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। इससे कारोबार, परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही इसका बोझ टैक्स भरने वालों पर पड़ेगा। हालांकि प्रशासन डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू कर चुका है। भारत के भी लगभग 18 हजार अवैध आप्रवासी वापस भेजे जाएंगे।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(घ) प्रतिष्ठया सार्वभौम सद्मना भुवनत्रयम्। पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्।। (श्रीमद्भागवत 11 । 27 । 52)

अर्थात् (क) सूर्य की पूजा करने से ही ब्रह्मा को ब्रह्मपद विष्णु को विष्णुत्व और महादेव को शंकरत्व प्राप्त हुआ है। (ख) वेद धर्मशास्त्र पुराण इतिहास और और अन्यान्य संनड़ों शास्त्र शिव- पुराण की किंचित् मात्र भी बराबरी नहीं कर सकते। (ग) विष्णु की प्रदक्षिणा करने में मनुष्य जितने कदम चलता है उतने हजार कल्प- पर्यन्त विष्णु भगवान् के साथ आनेन्द करता है (घ) भगवान् के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराने से चकवर्ती बनता है, मन्दिर बनवाने से तीन लोक का राजा होता है, पूजा करने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और तीनों कार्य करने से विष्णु के समान हो जाता है।

उपर्युक्त पुराण-वाक्यों में सूर्योपासना, शिव पुराण पठन, विष्णु- प्रदक्षिणा और देवालयनिर्माणरूप वर्मकार्यों में मनुष्यों की अभिरुचि बढ़ाने की चेष्टा की गई है। यदि कोई मनुष्य यहां कवि के आशय के विरुद्ध - (क) से ब्रह्मादि देवताओं का लघुत्व (ख) से वेदादि शास्त्रों की तुच्छता (ग) से प्रदक्षिणा का सर्वातिशायित्व और (घ) से प्रतिष्ठा आदि कराने पर भी चक्रवर्ती पद का न मिलना रूप मिथ्याभाषण सिद्ध करना चाहे तो उसे शास्त्रशैली से अनभिज्ञ ही समझना चाहिए । इसलिए जिस प्रकार वेदर्वाणत %अर्थवादों% का ग्राक्षरिक अर्थ ग्रहण न करके तात्पर्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार पुराणान्तर्वर्ती रोचक वचनों का भी तात्पर्यार्थ ही ग्र%ण करना चाहिए ।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

ब्रह्मानंद राजपूत

भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी 'भारत निर्वाचन आयोग' की होती है। 'भारत निर्वाचन आयोग' का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था। और भारत में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव

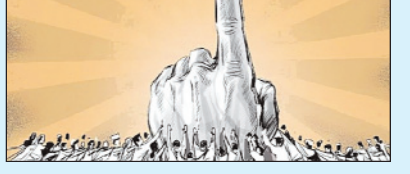

कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था, इसलिए 25 जनवरी, 1950 को 'भारत निर्वाचन आयोग' गठन हुआ।

'भारत सरकार' ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस '25 जनवरी' को ही 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। और 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में सरकारों और अनेक सामजिक संथाओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिससे कि देश की राजनैतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कि जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है। क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकारें बदल देता है। हम सबका एक वोट ही पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधि भी चुन सकता है और एक बेकार प्रतिनिधि भी चुन सकता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। भारत देश की 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि साप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचें। जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा उस दिन देश से जातिवाद, ऊँच-नीच, साम्प्रदायिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है हम सबके मतदान करने से। 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्रत, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परम्परा को बरकरार रखेंगे। और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। ऐसी शपथें हर वर्ष 25 जनवरी को लाखों लोग लेते हैं। लेकिन फिर भी इस शपथ पर अमल बहुत कम होता है।

सिंधु जल संधि का विवाद कौन सुलझाएगा?

साहिबा खान

भारत और पाकिस्तान लंबे समय से सिंधु जल संधि या इंडस वॉटर ट्रीटी पर झगड़ते आ रहे हैं। संधि के इर्द गिर्द कई ऐसे मसले हैं जो दोनों देशों को सुलझाने हैं। इन्हीं मसलों में से दो मुद्दे सुलझाने के लिए 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक निष्पक्ष विशेषज्ञ को चुना था। अब उनकी भी रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञ संधि के तकनीकी मुद्दों को सुलझाने का हुनर रखते हैं। भारत के लिए यह खबर अच्छी है क्योंकि भारत चाहता था कि निष्पक्ष विशेषज्ञ ही योजनाओं के विवादों पर फैसला दें।

दरअसल सिंधु जल संधि के तहत कई छोटी नदियां और उन पर बने या बन रहे पनबिजली प्रोजेक्ट पर विवाद छिड़ा हुआ है। ये विवाद बहुत पुराना है। लेकिन अब मसला यह है कि इन विवादों को कौन सुलझाएगा।

संधि में सभी नदियों को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया। सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी पश्चिम की नदियां पाकिस्तान के और रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में आईं। 2007 में भारत ने झेलम नदी पर किशनगंगा बांध बनाने की शुरुआत की। इससे पाकिस्तान के लिए नदी में पानी की कमी हो सकती थी। इसलिए पाकिस्तान ने 2010 में वर्ल्ड बैंक से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना कर इस मसले को सुलझाने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के अनुसार झेलम पर बांध बना कर और नदी का रुख मोड़कर भारत संधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। जिसके कारण नदी में पाकिस्तान के लिए पानी कम पड़ सकता था।

पर्यावरण विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर ने डीडब्ल्यू से बातचीत में बताया कि किशनगंगा बांध का मुद्दा पहले ही आर्बिट्रेशन अदालत में जा चुका था। उन्होंने कहा, उस वक्त अदालत ने फैसला दिया कि भारत बांध तो बना सकता है लेकिन उसमें भी कई शर्तें मौजूद थीं जिन्हें ध्यान में रखते हुए भारत को बांध बनाना था। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में किशनगंगा बांध का उद्घाटन किया। साथ ही भारत ने चेनाब नदी पर रातले पनबिजली बांध भी बनाना शुरू कर दिया।

यह देखते हुए पाकिस्तान ने फिर 2016 में वर्ल्ड बैंक से एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने की बात कही। पाकिस्तान का कहना है कि इन दोनों परियोजनाओं में बांधों के डिजाइन संधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठक्कर ने कहा, अब सालों बाद मसला यह है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अदालत द्वारा बताई गई शर्तें सही से लागू नहीं हो रही हैं। तो पाकिस्तान के नजरिये से अगर यह मुद्दा पहले ही अदालत में जा चुका था तो उसे वहीं से दोबारा उठाना चाहिए।

पाकिस्तान मुद्दों को सुलझाने के लिए सबसे पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता अदालत जाना चाहता है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि पहले मसले को परमानेंट इंडस कमीशन यानी कि पीआईसी के पास सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, जो संधि के तहत बनी है।अगर फिर भी मसला हल नहीं होता है तब वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि एनई नियुक्त करेगा जो विवाद को सुनेगा और अगर मसला तब भी हल नहीं होता है तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मदद ली जाएगी।

हिमांशु ठक्कर बताते हैं कि पूरे समझौते में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे और उसके बाद ही अदालत में। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान का मानना है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उनका फैसला बाध्यकारी नहीं होता। इस बात पर ठक्कर कहते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल एक्सपर्ट और अदालत, दोनों का ही फैसला बाध्यकारी होता है। हिमांशु ने विश्व बैंक की नाकामी पर बात करते हुए बताया, विश्व बैंक ने छह साल लगा दिए किशनगंगा बांध के मसले को सुलझाने में। आज भी उन्ही मुद्दों पर दो देश फिर से भिड़ रहे हैं।

2023 में नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) ने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल पर भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया था।पाकिस्तान की शिकायत थी कि भारत सिंधु नदी पर जो बांध बनाता है उससे उसके यहां तक पहुंचने वाले पानी में कमी आएगी। उसकी 80 फीसदी खेती की सिंचाई इसी नदी पर निर्भर है।

उस समय भी भारत ने इस फैसले को खारिज किया था और उसकी योग्यता पर सवाल उठाए थे। शायद इसलिए भारत अब अदालत जाने की बजाये न्यूट्रल एक्सपर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। ठक्कर कहते हैं कि इसका हल ये नहीं कि फैसला खारिज कर दिया जाये। वो आगे कहते हैं, बल्कि आप दोनों जगह अपने तर्क रखें, उन्हें जीतें और मामला खत्म करें। यह एक अदालत है और बाकी अदालतों की तरह ही अगर आप इसमें सुनवाई पर नहीं आते हैं तो उससे मामला खत्म नहीं हो जाता।

19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। संधि में रेखांकित किया गया था कि कैसे भारत और पाकिस्तान, दोनों सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करेंगे।

संधि में लिंक नहरों, बैराजों और ट्यूबवेलों के लिए धन जुटाने और निर्माण के लिए भी प्रावधान शामिल किए थे। खास तौर से सिंधु नदी पर तारबेला बांध और झेलम नदी पर मंगला बांध पर। इनसे पाकिस्तान को उतनी ही मात्रा में पानी लेने में मदद मिली जो उसे पहले उन नदियों से मिलती थी जो संधि के बाद भारत के हिस्से में आ गई थीं।

ज्यादातर धन की व्यवस्था वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों के योगदान से संभव हो पाई। संधि को ठीक से लागू करने और दोनों देशों के बीच एक बातचीत का जरिया बनाए रखने लिए हर एक सदस्य देश से एक एक आयुक्त नियुक्त हुआ। फिर इनसे एक स्थायी सिंधु आयोग (परमानेंट इंडस कमीशन) बनाया गया। इसके अलावा, विवादों को सुलझाने के लिए भी एक तंत्र बनाया गया था।

यह नौबत इसलिए आई क्योंकि 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच पानी पर विवाद हो गया था। 1 अप्रैल 1948 से भारत ने, अपने इलाके से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोकना शुरू कर दिया। तब 4 मई 1948 को विवाद निपटाने के लिए एक इंटर-डोमिनियन समझौता हुआ जिसके तहत भारत को सालाना भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी हिस्सों को पानी उपलब्ध कराना था। हालांकि यह रास्ता स्थाई नहीं था, बस एक ऐसा तरीका था जहां से विवाद निपटाने का काम शुरू होकर और आगे जाना था।

फिर आखिरकार 1951 में टेनेसी वैली अथॉरिटी और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग दोनों के पूर्व प्रमुख डेविड लिलिएनथल ने अपने लेखन के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया। तब उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान को नदियों पर एक तंत्र का साथ में विकास और फिर उसका प्रबंधन देखना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक समझौते का सुझाव दिया। उन्होंने सुझाया कि इस समझौते पर सलाह और धन वर्ल्ड बैंक दे सकता है।

यूजीन ब्लैक उस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। 1954 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को एक प्रस्तावित समझौता थमाया। इस पर छह साल तक कई दौर की बातचीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अय्यूब खान ने 1960 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही सिंधु नदी जल संधि प्रभाव में आई।

विवाद सिर्फ नदियों पर बांध बनाने के लिए नहीं है। विवाद की एक वजह है भारत का संधि की शर्तों में बदलाव की इच्छा। सितंबर, 2024 में भारतीय अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने फैसला किया कि आईडब्ल्यूटी पर दोबारा बातचीत होने तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों से बने पीआईसी की कोई और बैठक नहीं होगी। आखिरी बैठक मई 2022 में दिल्ली में हुई थी।

2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, दोनों ही नियुक्त कर दिए थे, लेकिन आगे यह भी कहा था कि इन दोनों के फैसले एक दूसरे से उलट भी हो सकते हैं। हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि यह फैसला भी विश्व बैंक की नाकाम कोशिशों को दिखाता है। जब आपने पहले ही बोल दिया है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट और अदालत का फैसला एक दूसरे के उलट आ सकता है तो आप एक साथ सामान विवादों की चर्चा दोनों जगह क्यों कर रहे हैं?

भारत का कहना है कि वह अब भी न्यूट्रल एक्सपर्ट के फैसले को ही मानेगा, वहीं पाकिस्तान द हेग की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर अड़ा है। जनवरी 2023 से अब तक भारत ने संधि में संशोधन पर बातचीत शुरू करने के लिए पाकिस्तान को चार बार चिट्ठी लिखी है लेकिन अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

आज का इतिहास

1824 प्रसिद्ध बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म हुआ।
1871 कॉकेशिया के संघर्षकर्ता धर्मगुरु शैख़ शामील का मदीना नगर में निधन हुआ।
1881 थॉमस एडीसन और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी की स्थापना की।
1881 थॉमस अल्वा एडीसन और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी बनायी।
1890 अस्सी दिनों में जूल्स वर्ने के आसपास दुनिया से प्रेरित होकर, अमेरिकी पत्रकार नेली बेली ने तब के रिकॉर्ड 72 दिनों में दुनिया के एक पूर्वनिर्धारण को पूरा किया।
1904 पेंसिल्वेनिया के चेस्विक में कोयला खदान विस्फोट में 179 लोगों की मौत हो गयी।
1924 फ्रांस के शैमॉनिक्स में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ।
1939 चिली के चिलान में भूकंप से 10 हजार लोग मारे गये।
1947 प्रसिद्ध गैंगस्टर अल कैपोन मरा।
1949 एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने अमेरिकी टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता के लिए पहला एमी पुरस्कार प्रदान किया।
1952 बंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ।
1955 अमेरिका और पनामा ने नहर संधि पर हस्ताक्षर किये।
1971 युगांडा में आठ साल के सैन्य शासन की शुरुआत करते हुए, राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे से एक सैन्य तख्तापलट में ईदी अमीन दादा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया।
1990 एवियनका फ्लाइट 52 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईंधन से बाहर चला गया और कोव नेक के गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 73 लोगों की मौत हो गई।
1993 वर्जीनिया के लैंगली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी मुख्यालय के बाहर पांच लोगों को गोली मार दी गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई।
1995 नॉर्वेजियन और अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ब्लैक ब्रेंट XII साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जिसे रूसी सेना द्वारा ट्राइडेंट मिसाइल के लिए गलत किया गया था।
1998 ग्रीस, यूजीन ओ नील थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में बंद हुआ। यह 1,503 प्रदर्शनों के बाद बंद हुआ।
1999 कोलंबिया में पिछले 16 वर्षों में आया एक भूकंप में 300 लोगों की मौत हो गई जबकि एक हज़ार लोग घायल हुए।
1999 कोलंबिया भूकंप की चपेट में है। यह बताया गया है कि आर्मेनिया में 1,185 मारे गए थे।
2004 मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ऑपर्च्युनिटी मंगल पर उतरा और ईगल क्रेटर, मेरिडियानी प्लैनम पर एक छोटा गड्ढा में लुढ़का।
2010 इथियोपिया के अदीस अबाबा के लिए इथियोपिया एयरलाइंस की उड़ान 409, लेबनान के बेरूत से टेकऑफ के तुरंत बाद भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 90 लोगों की मौत हो गई।

नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम के मिलने लगे हैं बेहतर नतीजे

कमलेश पांडे

आमतौर पर नक्सली, आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड अपने पूरे जमात के साथ भारतीय गणतंत्र के लिए चुनौती समझे जाते हैं। इसलिए सुरक्षाबलों ने 76वें गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाए हैं और एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वह तिरंगे और संवैधानिक गणतांत्रिक व्यवस्था को सच्ची सलामी है। इसलिए देशवासियों की अपेक्षा है कि सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई और अधिक तेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम उनके नापाक हौसले को तोड़ सकते हैं।

देखा जाए तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय थल या समुद्री सीमा से सटे प्रदेश हों या हमारे आंतरिक प्रदेश, यहां पर नक्सलियों, आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की मौजूदगी और उनके मार्फ़त जब-तब होते रहने वाली हिंसात्मक घटनाएं एक ओर जहां शासन व्यवस्था और अमनपसंद लोगों को मुंह चिढ़ाती हैं, वहीं दूसरी ओर धनी लोगों के भयादोहन का कारण भी बनती हैं। चूंकि अवैध मानव व वस्तु तस्करी, ड्रग्स सिंडिकेट, अवैध हथियारों के कारोबार, फिरौती, विवादास्पद सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त आदि से इनके तार जुड़े होते हैं, इसलिए सफेदपोश नेताओं-समाजसेवियों-कथित अधिकारियों-उद्योगपतियों आदि के माध्यम से इनके सरगना भी परस्पर मिले हुए होते हैं।

आम धारणा रही है कि इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं से इनकी गुप्त सांठगांठ रहती है! और यही इनके तार कथित राष्ट्रीय नेताओं और अर्बन नक्सलियों-अपराधियों-आतंकवादियों के सिंडिकेट तक से जोड़ते हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी सियासी कारणों के चलते इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्यों की आतंकी घटनाएं हों, या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार की नक्सली घटनाएं, या फिर बड़े महानगरों से लेकर जिलास्तरीय शहरों की अंडरवर्ल्ड वारदातें, इनके तार परस्पर जुड़े बताए जाते हैं।

कहना न होगा कि इनमें से कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूती के पीछे भी इनकी राष्ट्रविरोधी सोच होती हैं, जिन्हें बरास्ता नेपाल, पाकिस्तान व चीन का भी संरक्षण हासिल होता है। वहीं, कांग्रेस समेत कई बड़े क्षेत्रीय दल भी इनके नेक्सस के समक्ष घुटने टेक चुके हैं। जबकि इन सभी बातों से उलट केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी भाजपा नीत एनडीए की सरकार और उड़ीसा-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की भाजपा प्रदेश सरकारों की संगठित अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रोत्साहित होकर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रणनीति बनाकर नक्सलियों-दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी एक झलक ताजा कार्रवाई से मिलती है। गौरतलब है कि भारत में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता तब मिली, जब गत दिनों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (ष्टक्रक्कस्न), छत्तीसगढ़ के एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और ओडिशा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 14 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से की गई त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हथियार और बाकी सामग्री भी बरामद की गई जो नक्सली गतिविधियों को और बढ़ावा दे रही थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों के इस संयुक्त ऑपरेशन में नक्सल आंदोलन का एक प्रमुख सरगना, जयराम चलपती को ढेर किया गया। क्योंकि जयराम को नक्सली हिडमा का गुरु माना जाता था और नक्सली गतिविधियों में उसकी अहम भूमिका थी। जयराम पर 1 करोड़ रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए जयराम की तलाश एक बड़ी चुनौती थी। ऐसा इसलिए कि वह

नक्सलवादी समूहों के लिए एक अहम रणनीतिक सोच के रूप में काम करता था। उसकी मृत्यु से न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा बल्कि पूरे देश में नक्सलवादी आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है।

बताया जाता है कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर जयराम और उसके साथी नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से सख्त अभियान चलाया था। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर इस सफलता पर बधाई दी और सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक और अहम कदम है।

बता दें कि भारत सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए। ये ऑपरेशन उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। समझा जा रहा है कि जयराम की मौत के बाद अब नक्सलियों के मनोबल को भारी झटका लगेगा और उन्हें पुनः अपनी ताकत को संगठित करना मुश्किल होगा। सुरक्षा बलों की ये सफलता न केवल एक बड़ी सैन्य जीत है बल्कि ये देश के नागरिकों के लिए एक संदेश भी है कि नक्सलवाद का खात्मा अब बिल्कुल नजदीक है। बता दें कि एक साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के रोडमैप को जो हरी झंडी दी थी, उसके तहत एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कुल 96 मामलों की जांच कर रही है। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और सटीक रणनीति का ही यह तकाजा है कि हाल ही में 14 नक्सली एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। उल्लेखनीय है कि एक साल पहले 21 जनवरी 2024 को गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व एवं सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी, जिसमें नक्सलवाद को खत्म करने के रोडमैप को हरी झंडी दी थी। वहीं, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के विपरीत नवनियुक्त विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस रोडमैप को अमली जामा पहनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित की, जिसका बेहतर नतीजा सबके सामने है।

गौरतलब है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाए गए अमित शाह के रोडमैप में तीन अहम बिंदू हैं। पहला, नक्सलियों के कोर इलाके में सुरक्षा बलों की अग्रिम चौकियां स्थापित कर सुरक्षा गैप को भरना, दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून का इस्तेमाल कर ईडी की मदद से नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग के स्त्रोत को पूरी तरह से बंद करना, और तीसरा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून का इस्तेमाल पर नक्सली गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ एनआईए की जांच कराकर कड़ा सजा सुनिश्चित करना। कहना न होगा कि तीनों ही फ्रंट में राज्य प्रशासन के सहयोग से बेहतरीन काम हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के बाद सुरक्षा बलों की 290 अग्रिम चौकियां स्थापित की गईं, जिनमें अकेले साल 2024 में 58 अग्रिम चौंकियां स्थापित करना शामिल हैं। वहीं, इस साल 2025 में सुरक्षा बलों की कुल 88 अग्रिम चौकियां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, राज्य सरकारें, ईडी और एनआईए ने नक्सल फंडिंग से जुड़ी 72 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है। वहीं, एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कुल 96 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 56 मामले पिछले तीन साल में दर्ज किये गए। इनमें से 77 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।

एक्सपर्ट बताते हैं कि कहने को अग्रिम सुरक्षा चौकियों का गठन छोटी बात लग सकती है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह कारगर रणनीति साबित हो रही है। क्योंकि अग्रिम सुरक्षा चौकियां बनने से उसके तीन-चार किलोमीटर के दायरे में नक्सलियों के लिए अपनी गतिविधि चलाना संभव नहीं रहता है। वहीं, दूसरी बात यह है कि इन चौकियों के सहारे सरकारी तंत्र और लोक कल्याणकारी व विकास योजनाएं भी ग्रामीणों तक पहुंच रही है। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक अबूझमाड़ से लेकर दंडकारण्य और उससे आगे तक फैले नक्सल प्रभाव वाले पूरे इलाके में हर तीन-चार किलोमीटर पर एक सुरक्षा अग्रिम चौकी स्थापित कर करने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि इन अग्रिम चौकियों का ही कमाल है कि वर्ष 2023 में जहां मात्र 50 नक्सलियों को मार गिराया गया था, वहीं उसकी तुलना में साल 2024 में 290 नक्सली मारे गए हैं। यही नहीं, इस साल 2025 में 21 जनवरी तक 48 नक्सली मारे जा चुके हैं।

इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2025 में स्थापित होने वाले नए 88 अग्रिम सुरक्षा चौकियों की स्थापना से सुरक्षा बलों के आपरेशन की ताकत में और इजाफा होगा। वहीं, अगले साल 2026 में प्रस्तावित सभी सुरक्षा चौकियों के बनने के बाद नक्सलियों के पास अपनी गतिविधि चलाने को कोई भी सुरक्षित क्षेत्र ही नहीं बचेगा। यही वजह है कि उसके बाद ही नक्सलवाद के खात्मे का एलान किया जाएगा। इससे साफ है कि अमित शाह की सटीक रणनीति ने बाजी उनके पक्ष में पलटती जा रही है, जिससे एक सफल गृहमंत्री के रूप में उनके नाम का शुमार किया जाने लगा है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों ने जो अभियान छेड़ रखा है, उसकी अनवरत कार्रवाइयों और सटीक रणनीति के कारण एक साल भीतर ही नक्सलियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं।

सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर देना होगा ध्यान

रमेश ठाकुर

लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सन 2008 में हुई थी। ये तारीख इसलिए मुकर्रर की गई, क्योंकि इसी दिन यानी 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली मर्तबा बतौर प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें 'सेव द गर्ल चाइल्ड', 'चाइल्ड सेक्स रेशियो' व 'चाइल्ड क्राइम प्रोटेक्शन' अभियानों के अलावा बालिकाओं के स्वास्थ्य और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने

सहित तमाम तरह की जागरूकता फैलाई जाती है जिसमें सामाजिक और सरकारी, दोनों धड़े अपनी सहभागिता करते हैं। किशोरियों की तस्करी एक बड़ी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में बताया था कि पूरे देश में अभी लाखों की संख्या में बच्चियों को उनके अभिभावक स्कूलों में नहीं भेजते। ये हाल तब है जब बच्चियों की शिक्षा पर केंद्र व राज्य सरकारें सजगता से लगी हुई हैं। बेटियों के सम्मान में केंद्र सरकार ने 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' का नारा दिया है। इससे बालिका लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। 2014 में बेटियों के जन्मानुपात का आंकड़ा 918 था, तो वहीं 2022-23 में ये आंकड़ा 933 तक जा पहुंचा। इस आंकड़े में हरियाणा अभी भी पिछड़ा हुआ है। देश की तरक्की में लड़कियों को लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करके भी दिखा दिया है। रक्षा से लेकर खेल तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बेटियां परचम न फहरा रही हों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार भारत में सालाना लाखों की संख्या में बच्चियां लापता होती हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चियों की उम्र महज 8-10 वर्ष होती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, साल 2019 से 2021 में 13 ।13 लाख गायब महिलाओं में ज्यादातर संख्या लड़कियों की रही। वहीं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बीते 5 वर्षों में 2 ।75 लाख बच्चे गुम हुए जिनमें से 2 ।12 लाख सिर्फ लड़कियां थीं। लापता बच्चों के मामले में पश्चिम बंगाल अव्वल है जहां साल-2022 में 12,546 लड़कियां गुम हुईं। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहां 11,161 किशोरियां गायब हुईं। बाकी प्रदेशों के हाल भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा बाल तस्करी, बाल विवाह और नाबालिगों के साथ यौन शोषण की घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं। इन्हें सामूहिक प्रयासों से ही मिलकर रोकना होगा।

मंगोलपुरी से चार बार कांग्रेस तो तीन बार आप को मिली जीत

संध्या

दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होने है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सभी पार्टियों में चुनाव को लेकर अब हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। आज आपको मंगोलपुरी विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में बताने जा रहा हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में मंगोलपुरी में कब कौन जीता? कब कितने वोट पड़े? पिछले चुनाव में कैसे नतीजे रहे थे? इस बार कैसा मुकाबला है? आइये जानते हैं

दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट-सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई। दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट-सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग-सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे।

दिल्ली के विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए। 1993 में यहां

भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर टक्कर थी। कांग्रेस के राजकुमार चौहान ने भाजपा के सोरन सिंह निराला को 7663 वोटों से हरा दिया था।

साल 1998 में भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही हुआ। कांग्रेस के राज कुमार चौहान को 32372 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के लक्ष्मी नारायण को 21,014 वोटों से हरा दिया था।

2003 में मंगोलपुरी सीट पर राज कुमार चौहान को लगातार तीसरी बार जीत मिली। कांग्रेस के राज कुमार चौहान ने बीएसपी के मेघ सिंह को 30,315 वोट से हरा दिया। 2003 के विधानसभा चुनाव में मंगोलपुरी सीट पर भाजपा तीसरे स्थान पर खिसक गई। भाजपा के राजू बाल्मिकी को 8,670 वोट से संतोष करना पड़ा।

2008 में मंगोलपुरी सीट पर चुनावों के नतीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक बार फिर यहां पर कांग्रेस ने ही विजय पताका फहराई। चौथी बार राज कुमार चौहान यहां से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के योगेश आत्रेय को 29,863 वोटों से हरा दिया।

दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। कांग्रेस ने अपनी मौजूदा विधायक और मंत्री को चेहरा बनाया था। उनके सामने आप के टिकट पर राखी बिड़ला चुनाव लड़ रही थीं।

राखी ने लगातार चार बार मंगोलपुरी से जीत दर्ज कर चुके कांग्रेस के राज कुमार चौहान को हरा दिया। आप की राखी बिड़ला को 10,585 वोट से जीत मिली। इसके बाद से कांग्रेस कभी इस सीट पर वापसी नहीं कर पाई।

2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।

इस चुनाव में मंगोलपुरी सीट पर राखी बिड़ला के सामने कांग्रेस के राज कुमार चौहान ही थे। आप ने कांग्रेस को 22,699 वोटों से हरा दिया। राखी बिड़ला को 60,534 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 37,835 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा।

2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। मंगोलपुरी के नतीजों की बात करें तो यहां से आप की तरफ से राखी बिड़ला को फिर से जीत मिली। आप उम्मीदवार ने भाजपा के करम सिंह कर्मा को 30,116 वोट से हरा दिया। राखी बिड़ला को 74,154 और भाजपा को 44,038 वोटों से साथ संतोष करना पड़ा।

अबकी बार कैसे हैं समीकरण?

2025 के चुनावों में आप ने इस बार यहां से आप ने राखी बिड़ला की सीट बदल कर राजेश जाटव धर्मरक्षक को मंगोलपुरी से टिकट दिया है। राजेश जाटव वार्ड 49 मंगोलपुरी ने निगम पार्षद हैं। भाजपा में हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए राजकुमार चौहान को टिकट दिया है। राज कुमार चौहान लगातार चार बार यहां से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वहीं, कांग्रेस ने हनुमान चौहान को टिकट दिया है।

समावेशी राजनीति के जननायक थे कर्पूरी

केसी त्यागी

दुनिया में कई ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं, जिनके कार्यों और विचारों को उनके समय के समाज ने पूरी तरह से समझा या स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके विचार और प्रयास अपने समय से कहीं आगे के थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनका देश शुक्रवार को 101वां जन्मदिवस मनाया, उन्हें भी उनके जीवनकाल में व्यापक स्तर पर कभी पूर्ण स्वीकार्यता नहीं मिली।

उन्हें सर्वमान्य नेता के बजाय दलित नेता और बाद में अति पिछड़ों के नेता के रूप में सीमित कर दिया गया क्योंकि उनका जन्म (24 जनवरी, 1924 को) नाई जाति में हुआ था। जीवनभर उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से अपमान का सामना करना पड़ा। जाति के कारण ही उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया था। उनके विरोधियों ने उन्हें तिरस्कारपूर्ण ढंग से 'कपटी ठाकुर' कहकर संबोधित किया, यह उनके प्रति सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह का प्रतीक था।' कर्पूरी ठाकुर कुल नौ बार विधायक और एक बार सांसद निर्वाचित हुए। वह बिहार की राजनीति में एक अजेय नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें अद्वितीय स्थान दिलाया। वर्ष 1967 में जब वे चौथी बार ताजपुर विधानसभा से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गयीं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआइ, जनक्रांति दल और प्रजा सोशलिस्ट जैसी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनायी। हालांकि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और उसके नेता कर्पूरी ठाकुर की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी थी।

डॉ राम मनोहर लोहिया भी चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनें, पर दूसरी पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं हुईं। दरअसल, वर्ष 1967 के विधानसभा चुनाव में केबी सहाय को महामाया प्रसाद सिन्हा ने पराजित किया था।

ऐसी स्थिति में सभी दलों ने जनक्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर सहमति जतायी और अंततः महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में कर्पूरी ठाकुर को पहली बार उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यहीं से गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किये। मैट्रिक की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की ताकि शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो सके। इस निर्णय से शिक्षा का दायरा व्यापक हुआ और समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने का अवसर मिला। हालांकि, उनके इस कदम की आलोचना हुई, और इसे विरोधियों ने 'कर्पूरी डिवीजन' कहकर व्यंग्यात्मक नाम दिया।

उन्होंने स्कूलों की फीस भी माफ की, जिससे गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में आर्थिक बाधाओं का सामना न करना पड़ा। ये निर्णय उनकी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। हालांकि इस सरकार को उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल स्वास्थ्य मंत्री बीपी मंडल और उनके साथी बाबू जगदेव प्रसाद ने गिरा दिया। वर्ष 1969 में कर्पूरी ठाकुर पांचवीं बार ताजपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए। दरोगा प्रसाद राय की सरकार गिरने के बाद वह संविद सरकार में पहली बार 22 दिसंबर, 1970 को मुख्यमंत्री बने। इस संविद सरकार में समाजवादी समता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस (ओ), जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, झारखंड पार्टी के विभिन्न गुट, शोषित दल, और हुल झारखंड जैसे कई दल शामिल थे।

कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में यह सरकार केवल छह महीने ही चली। इस कारण वे कोई बड़े बदलाव करने में असमर्थ रहे। वे आपातकाल के बाद 1977 में लगातार सातवीं बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। रिपोर्ट के तहत उन्होंने 12 प्रतिशत आरक्षण अति पिछड़े वर्ग, आठ प्रतिशत पिछड़े वर्ग, तीन प्रतिशत सभी वर्गों की महिलाओं और तीन प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू किया। इस प्रकार, कुल 26 प्रतिशत आरक्षण की नीति अस्तित्व में आयी। स्वतंत्र भारत में महिलाओं के लिए और सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब वर्गों के लिए पहली बार आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी। इस निर्णय के लिए उन्हें हर वर्ग की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भले ही उनकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें हटाया गया, पर उनके निर्णयों ने बिहार की राजनीति में एक नयी दिशा और सोच को जन्म दिया, जो आज भी विस्तार कर रही है। उनकी नीतियों का प्रभाव अन्य राज्यों और केंद्र स्तर पर भी देखा गया। कर्पूरी ठाकुर की नीतियां उन तबकों को अवसर प्रदान करती हैं, जो सामाजिक संरचना में सबसे वंचित, अदृश्य और बिखरे हुए हैं। ऐसे जातीय समुदायों के पास न तो राज्य स्तर पर प्रभावशाली सिविल सोसाइटी है और न ही केंद्र स्तर पर कोई संगठित राजनीतिक दल, जो उनकी असहमति, मांगों और समस्याओं को सामने ला सके। कर्पूरी ठाकुर की दूरदर्शिता सामाजिक न्याय के व्यापक सिद्धांतों को स्थापित करने और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने का आधार बनी। आज, जब हम आरक्षण नीति को लेकर बहस करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि इसके मूल में सामाजिक न्याय का वह गहरा दर्शन है, जो यह मानता है कि केवल संसाधनों का पुनर्वितरण ही नहीं, बल्कि सम्मान और समानता भी जरूरी है।

चांदनी चौक सीट पर लड़ाई रोचक

राहुल कुमार

चांदनी चौक दिल्ली की उन सीटों में शामिल है जो अपने साथ एक विरासत को समेटे हुए हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लालकिले के सामने बसे इस इलाके में दिल्ली की एक लंबी विरासत रहती है। दिल्ली आने वाला हर पर्यटक इस बाजार को घूमकर देखना चाहता है। यही कारण है कि इस इलाके में व्यापार, साफ-सफाई और व्यापार सबसे बड़ा मुद्दा हर चुनाव में रहता है। इस विधानसभा चुनाव में भी यहां पर साफ-सफाई, पर्यटन और रोजगार के मुद्दे छाए हुए हैं। चांदनी चौक प्रह्लाद साहनी की सीट मानी जाती है। 1998 से 2013 के बीच उन्होंने इस सीट पर लगातार चार बार जीत हासिल की। इसके बाद 2015 के चुनाव में अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर इस सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन इसके अगले चुनाव यानी 2020 में प्रह्लाद सिंह साहनी ने एक बार फिर जीत हासिल की, लेकिन इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर यह जीत हासिल की। पांच बार जीत हासिल कर चुके प्रह्लाद सिंह साहनी का टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिया है। इस बार उनके ही परिवार के पूरनदीप सिंह साहनी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। इसलिए पहली नजर में प्रह्लाद सिंह साहनी के असर के कारण उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल एक व्यापारी नेता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी सीट से बड़ी जीत हासिल की थी, वे इस बार अपने इलाके से भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इस बार भाजपा उम्मीदवार सतीश जैन को भी यहां मजबूत खिलाड़ी माना जा रहा है। लेकिन इन दो मजबूत खिलाड़ियों को सबसे तगड़ी चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल से मिल रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल अपनी बेबाक छवि और पिता की राजनीतिक विरासत के सहारे यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि, वे इसी जमीन पर पले-बढ़े हैं, यहां का एक-एक मतदाता उनकी पहचान का है और यही उनकी ताकत है। मुदित अग्रवाल ने अमर उजाला से कहा कि चांदनी चौक विधानसभा सीट केवल चुनावी क्षेत्र नहीं है यह एक ऐतिहासिक विरासत भी है। चांदनी चौक में कई ऐसे स्मारक (मॉन्यूमेंट्स) है जिनसे हमारे देश और उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता होगी कि चांदनी चौक को हेरिटेज हब बनवाया जाए। इससे यहां पर रोजगार के साथ-साथ इसका महत्त्व भी बढ़ेगा। मुदित अग्रवाल ने कहा कि चांदनी चौक में दिल्ली और देश का इतिहास बसता है। यह केवल चुनावी क्षेत्र ही नहीं है एक विरासत भी है। समय के साथ-साथ इस क्षेत्र का विस्तार होता गया साथ ही यहां की समस्याएं भी बढ़ती गई हैं, लेकिन इनका निदान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से चांदनी चौक दिल्ली का प्रमुख एरिया माना जाता है। यहां देश-विदेश से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। वहीं, भाजपा नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल की है, उसी तरह इस बार भी वह यहां पर बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। वह बदलाव की ओर देख रही है। चांदनी चौक के लोगों को केवल विकास चाहिए। वह विकास उन्हें भाजपा के साथ नजर आता है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के कारण अब खत्म हो चुकी है और कांग्रेस अब लोगों की उम्मीदें पूरी करने में सक्षम नहीं है।

संतरे से ज्यादा इन 6 फलों में होती है विटामिन सी की मात्रा,आज ही करें अपनी डाइट में शामिल,मिलेंगे गजब के फयदे

विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। वहीं अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो व्यक्ति को थकान, कमजोरी, मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द जैसे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। यूएसडीए के अनुसार, एक संतरा व्यक्ति की दैनिक खुराक को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त होता है। यही वजह है कि जब कभी शरीर में विटामिन सी की कमी पूरी करने की बात होती है तो लोग सबसे सबसे पहले संतरे को एक अच्छा फल मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, संतरे के अलावा 5 ऐसे अन्य फल भी हैं, जिनमें संतरे से ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। आइए जानते हैं उनके बारे में।

अनानास

अनानास में प्रति 100 ग्राम 47.8 मिलीग्राम विटामिन सी होता है और संतरे में 45 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

कीवी

पोषण विशेषज्ञों के अनुसार लगभग दो कीवी में 137 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। कीवी प्रीबायोटिक्स का एक समृद्ध स्रोत है, जो पाचन तंत्र में प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया और यीस्ट के विकास के लिए आवश्यक हैं।

जामुन

जामुन में मौजूद विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ाने, घाव भरने, स्किन में कोलेजन का उत्पादन करने और आयरन के अवशोषण में मदद करती है। जामुन में विटामिन सी की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। बता दें जामुन में प्रति 100 ग्राम में लगभग 80-90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

पपीता

पपीता विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। पपीते में विटामिन सी की मात्रा इतनी होती है कि यह दैनिक जरूरत से 1.5 गुना ज्यादा होता है। पपीते में मौजूद विटामिन सी, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।

बेर

इस छोटे, खट्टे फल में प्रति 100 ग्राम में लगभग 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो इसे एक हेल्दी नाश्ता बनाता है।

आंवले

आंवले में विटामिन सी की मात्रा 100 ग्राम में 500 से 700 मिलीग्राम होती है। यह विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत है, जो हमेशा बना रहता है। जबकि संतरा या नींबू जैसे अन्य विटामिन सी रिच फलों में हवा या धूप के संपर्क में आने पर विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है।

बिना मेहनत के तेजी से बजन घटाने के लिये बेस्ट है अदरक की चाय या ग्रीन टी,जाने इस्तेमाल करने का तरीका

जब भी वेट लॉस की बात आती है तो आप क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, यह बहुत अधिक मायने रखता है। अमूमन वेट लॉस के लिए दो बेहद ही पॉपुलर ड्रिंक हैं, ग्रीन टी और अदरक की चाय। ये दोनों ही ताजगी देने वाली हैं, जिनसे कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जहां ग्रीन टी कैटेचिन और कैफीन के कारण मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके अधिक फैट बर्न करने में मदद करती है, वहीं अदरक की चाय का थर्मोजेनिक प्रभाव होता है जो भूख को कम करने, पाचन में सुधार करने और सूजन को दूर करने में मदद करता है।इस बात में कोई दोराय नहीं है कि अदरक की चाय और ग्रीन टी दोनों ही वेट लॉस मे मददगार हैं। लेकिन अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि वे इन दोनों में से किसका सेवन करें। जहां कुछ लोग ग्रीन टी की सिफारिश करते हैं तो कुछ लोगों के लिए अदरक की चाय अधिक बेहतर है। तो चलिए आज इस लेख में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ईएसआईसी अस्पताल की डाइटीशियन रितु पुरी आपको बता रही हैं कि वेट लॉस के लिए ग्रीन टी या अदरक की चाय में से किसका सेवन करना ज्यादा बेहतर रहेगा

ग्रीन टी के वेट लॉस में फायदे

ग्रीन टी अपने कैटेचिन, विशेष रूप से एपिगैलोकैटेचिन गैलेट के लिए जानी जाती है। कैटेचिन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मददगार है, जिससे फैट बर्न करना अधिक आसान हो जाता है। साथ ही, इसमें थोड़ा कैफीन होता है जो आपका एनर्जी लेवल बनाए रखता है। अधिक एक्टिव रहने से भी वेट लॉस में मदद मिलती है।

कब पीएं ग्रीन टी?

आप वर्कआउट या भोजन से पहले एक कप ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं। यह फैट बर्न करने और पाचन को बेहतर बना सकती है। ग्रीन टी को दिन में दो से तीन कप पिया जा सकता है। आप इसमें शहद या नींबू भी मिक्स कर सकते हैं।

ग्रीन टी के नुकसान

अगर ग्रीन टी का अधिक सेवन किया जाता है तो इससे आपकी नींद खराब हो सकती है या कैफीन के कारण पेट खराब हो सकता है।

अदरक की चाय के वेट लॉस में फायदे

अदरक की चाय को वेट लॉस के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह एक नेचुरल थर्मोजेनिक है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर को गर्म करता है, जिससे अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह अतिरिक्त भूख को कम करने के साथ-साथ पाचन को बेहतर बनाता है।

कब पीएं अदरक की चाय?

आप अदरक की चाय को सुबह या मील्स के बीच में ले सकते हैं। इसे दिनभर में एक से दो कप पिया जा सकता है। टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें दालचीनी या नींबू निचोड़ें।

अदरक की चाय के नुकसान

अगर अदरक की चाय का जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाता है तो इससे आपको हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है।

किसका करें सेवन?

ग्रीन टी और अदरक की चाय दोनों ही वेट लॉस में कारगर है। आप इनके गुणों के आधार पर इनका चयन करें। मसलन-

मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के गुणों और कैटेचिन की वजह से ग्रीन टी थोड़ी बेहतर है।

अदरक की चाय आपके पेट को आराम देने और सूजन को कम करने के लिए सबसे बढ़िया है।

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो ओवर ऑल हेल्थ और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है।

वहीं, अदरक की चाय एंटी-इंफ्लेमेटरी होती है, जो कसरत के बाद मांसपेशियों के दर्द में आराम दिलाने में मदद करती है।

बेहतर रिजल्ट के लिए आप दोनों का सेवन कर सकती हैं। अतिरिक्त फैट बर्न के लिए वर्कआउट से पहले ग्रीन टी लें और पाचन को शांत करने और फूड क्रेविंग को कमम करने के लिए भोजन के बाद अदरक की चाय ली जा सकती है।

सर्दियों में रोज़ाना पीयें यह जूस,सेहत बनी रहेगी टनाटन,नहीं लगाने पड़ेंगे डॉक्टर के चक्कर

सर्दियों में फिट और हेल्दी रहने के कई ऑप्शन होते हैं. इस समय गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद और मटर जैसी कई सब्जियां होती है, इसमें मौजूद पोषक तत्व सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आप इन्हें सलाद के तौर पर भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सलाद खाना पसंद नही है तो आप इन सब्जियों का जूस बनाकर पी सकते हैं.ताजे फल और सब्जियों के जूस सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है. तरे का जूस, नींबू का जूस, और आमला जूस में विटामिन सी होता है ऐसे में ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं अलग जूस की अपनी अलग विशेषता होती है. आज हम आपको कुछ ऐसी जूस के बारे में बताने जा रहे हैं जो सर्दियों के मौसम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

गाजर और चुकंदर का जूस

गाजर और चुकंदर का जूस में आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. ये जूस आपकी स्किन और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप 4 गाजर, 1 चुकंदर, हरी धनिया, 1 आंवला, अदरक, स्वाद अनुसार काला नमक और चीनी मिलाकर जूस बना सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

आंवले का जूस

आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ ही स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. सर्दियों में आप आंवला और चुकंदर, आंवला और एलोवेरा, आंवला और लौका, गाजर और आंवला का जूस बनाकर भी सकते हैं.

चुकंदर, गाजर, अदरक, और सेब का जूस

चुकंदर, गाजर, अदरक, और सेब का जूस के सूज को एबीसी जूस भी कहा जाता है. इस जूस को पीने से इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिल सकती है. वहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी और कई पोषक तत्व मौजूद होते है, जो आपकी स्किन, होयर और ओवर ऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

संतरे का जूस

संतरे में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकता है. आप गाजर, हरा सेब, और संतरा इसके अलावा संतरे, मौसंबी, आंवले का जूस भी पी सकते हैं. लेकिन लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां, एसिडिटी की समस्या और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का इस जूस का सेवन करने से बचना चाहिए.

सर्दियों में इन तरीकों से डाइट में शामिल करें तिल,मिलेंगे गजब के फायदे,तेजी से कम होगा बजन

ठंड में ज्यादातर लोग तिल या तिल से बनी चीजों को खाना पसंद करते हैं। तिल के लड्डू से लेकर तिल की गजक तक, तिल सर्दियों के सुपरफूड में से एक है। तिल में प्रोटीन, आयरन, विटामिन, ओमेगा 6, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये शरीर को गर्म रखने के साथ ही एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा पेट से जिद्दी चर्बी को कम करने के लिए भी तिल काम आ सकती है। इसे खाने से भूख को नियंत्रित किया जा सकता है। पेट की जिद्दी चर्बी और वजन कम करने की सोच रहे हैं तो तिल को खाने में शामिल करें। यहां जानिए किन तरीकों से आप तिल को डायट में शामिल कर सकते हैं।

1) स्मूदी में शामिल करें - तिल के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसे आप सुबह की स्मूदी में मिला सकते हैं। स्मूदी में इसका एक बड़ा चम्मच मिलाने से पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। यह आपकी स्मूदी का स्वाद और बनावट दोनों बढ़ा देगा। तिल के बीज हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर होते हैं, जो आपको लंबे समय तक तृप्त रखेंगे।

2) सलाद में डालें - आप अपने सलाद को तिल के बीज के साथ और भी ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं। हेल्दी फैट और फाइबर के साथ, तिल आपके सलाद में कुरकुरापन जोड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, एवोकाडो में तिल मिलाने से फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है।

3) तिल से बनाएं बार - घर का बना ग्रेनोला बार हेल्दी स्नैक के तौर पर खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ओट्स, मेवे और मुट्ठी भर तिल भून लें। थोड़ा सा शहद मिलाएं और बेकिंग ट्रे पर इसे फैला लें। इसे बेक करें और टेस्टी बार तैयार है। इसे खाकर वजन मेनेज करने में मदद मिलती है।

उंगलियों की ये 5 एक्सरसाइज आपको बना देंगी जीनियस,तेजी से बढ़ेगा दिमाग

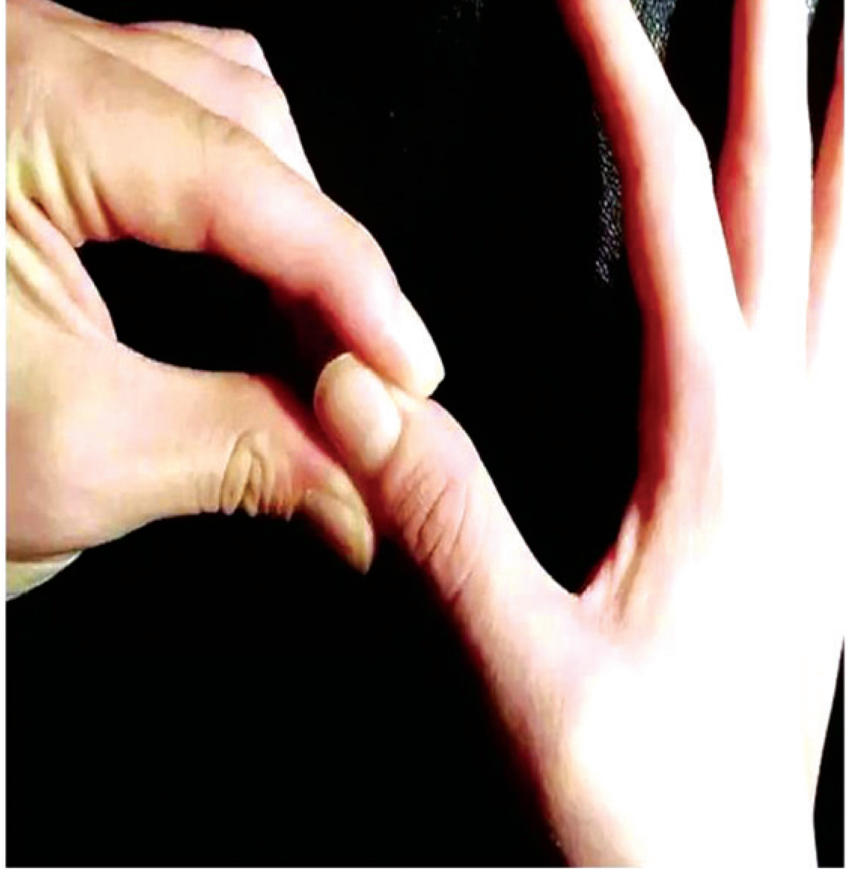

बढ़ती उम्र में व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होना एक कॉमन समस्या है। लेकिन आजकल की भागती-दौड़ती टेंशन भरी लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में ही लोगों को भूलने की बीमारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ वयस्कों में देखी जा रही है बल्कि बच्चे भी इस समस्या से अछूते नहीं रह गए हैं। बच्चों के लिए भी चीजें याद रखना मुश्किल होता जा रहा है। जिसकी वजह से वो कई बार अपनी कक्षा में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी छोटी-छोटी चीजें अकसर भूल जाते हैं या आपको किसी चीज को याद रखने में कठिनाई होती है तो अपनी उंगलियों का यूज करना शुरू कर दीजिए। जी हां, दिमाग तेज करने और याददाश्त बढ़ने के लिए ये 5 आसान फिंगर मूवमेंट आपकी मदद कर सकती हैं।

पहली एक्सरसाइज

दिमाग तेज करने वाली अपनी पहली फिंगर मूवमेंट में आपको एक हाथ की सभी उंगलियों को चोंच के आकार में एक दूसरे के साथ मिलाएं और दूसरे हाथ की हथेली के बीच में चिड़ियां की तरह चोंच मारे। इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों से एक-एक करके 50 बार दोहराएं। ऐसा करने से एकाग्रता बढ़ने के साथ मेमोरी बूस्ट होती है।

दूसरी एक्सरसाइज

अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाएं और दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा लें। इस दौरान आपकी दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुड़ी हो। अब पहले अपने दाएं हाथ की उंगलियों को एक साथ उठाएं, फिर इस हाथ की उंगली को वापस बंद करें और दूसरे हाथ की उंगलियों को उठाएं। इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 मिनट तक करें। ऐसा करने से तनाव कम होने के साथ एंजायटी भी कंट्रोल रहती है।

तीसरी एक्सरसाइज

दिमाग तेज करने के साथ डिसीजन मेकिंग को भी अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये तीसरी फिंगर ऑपोजिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक-एक करके अपनी सभी उंगलियों से अपने अंगूठे को छूएं।

चौथी एक्सरसाइज

मस्तिष्क को शांत रखने के लिए इस चौथी एक्सरसाइज में %ज्ञान मुद्रा योग% जैसी तकनीक का अभ्यास करें। इस मुद्रा में दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठों का उपयोग किया जाता है।

पांचवीं एक्सरसाइज

गुस्से पर कंट्रोल और ओवरथिंकिंग की समस्या को कम करने के लिए आप ये पांचवीं एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले अपनी सभी उंगलियों को मिलाकर हथेली को सीधा रखें। इसके बाद उंगलियों को चोंक के आकार में बनाए और इसके बाद मुट्ठी बना लें। इस फिंगर मूवमेंट को 2 मिनट तक करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम सत्यापन की मांग का मामला

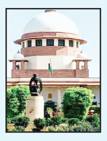

नई दिल्ली। ईवीएम सत्यापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और पांच बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। शुक्रवार को यह याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाए। जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था, उनका पालन किया जाए।

रची जा रही केजरीवाल की हत्या की साजिश : आप

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर कई हमलों का आरोप लगाते हुए भारत चुनाव आयोग से शिकायत की है। सीएम आतिशी ने कहा कि इस साजिश के पीछे दो खिलाड़ी हैं- एक हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और उन पर पथराव करते हैं, दूसरा खिलाड़ी दिल्ली पुलिस है जो बीजेपी और अमित शाह के अधीन आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद उनकी सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस लेने पर आप के राष्टीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह शुद्ध राजनीति है। यह खेदजनक है कि व्यक्तिगत सुरक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है।

मिल्कीपुर के रण में उतरे योगी सपा पर किया तीखा वार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने माफियाओं को बढ़ावा दिया और अब महाकुंभ मेले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के पावन धाम जनपद अयोध्या जी के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र के हर बूथ पर खिलेगा कमल का फूल। योगी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एक बार समाजवादियों के बारे में कहा था कि जो कोई भी धन की चाह में फंस जाता है वह सच्चा समाजवादी नहीं है। आज के समाजवादी केवल संपत्ति के मामले में उलझे हुए हैं। उनके झंडे जगह-जगह खाली भूखंडों पर लगाए जाते थे। उनके झंडे अपराधियों और माफियाओं को बचाने के लिए थे।

महाराष्ट्र को जल्द ही मिलेगा तीसरा उपमुख्यमंत्री : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उपमुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति शिवसेना (शिंदे गुट) से निकलेगा। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राउत ने यह बयान शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। राउत ने राज्य के भीतर एक आसन्न राजनीतिक विकास का संकेत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम मिलेगा। यह उनमें (शिवसेना-शिंदे) में से कोई होगा। उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के नेता राउत ने शिंदे गुट पर कटाक्ष किया। उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय ब्यूरो जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से दलबदल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग ईडी और सीबीआई के डर से भाग गये। अपने गुट के लचीलेपन की पुष्टि करते हुए, राउत ने कहा, सत्ता आती है और जाती है, लेकिन हम यहां अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं।

मुझ पर केजरीवाल ने ही हमला करवाया था : स्वाति मालीवाल

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला किया और उन पर बिभव कुमार को बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने का आरोप लगाया। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच स्वाति मालीवाल ने कहा कि पता चला कि पंजाब सरकार बिभव कुमार को जेड+ सुरक्षा मुहैया करा रही है। ये वही गुंडा है जिसने मुझे अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बेरहमी से पीटा था। स्वाति मालीवाल ने आगे दावा किया कि इन 6 महीनों में अब मैं पूरी तरह से मानने लगी हूं कि मुझ पर यह हमला अरविंद केजरीवाल ने ही करवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह विभव कुमार को इस तरह क्यों बचाते? उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गए तो देश को बता देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ही उन्हें कहा था कि मुझे मारो।

मोदी-मैक्रों की मुलाकात को लेकर आ गया विदेश मंत्रालय का बयान

कहा- हमने फ्रांस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है

नईदिल्ली। पीएम मोदी के मैक्रों के साथ पिछली मुलाकात 18 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी20 समिट के दौरान हुई थी। इससे पहले वह जनवरी में वतौर गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट और उसके वाद जुन में इटली में त्र7 समिट के दौरान दोनों नेताओं के वीच मुलाकात हुई थी। इससे पहले एआई समिट 2024 में साउथ कोरिया में हुआ था। डिफेंस डील होगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि फ्रांस एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैक्रों ने बताया था कि फ्रांस 11-12 फरवरी तक एक एआई समिट आयोजित करेगा। इस समिट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अंतर्राष्टीय चर्चा भी होगी। मैक्रों ने ये भी कहा था कि इस सम्मेलन के जरिए फ्रांस को अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों से संवाद करने में मदद मिलेगी।

बता दें कि पीएम मोदी के मैक्रों के साथ पिछली मुलाकात 18 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी20 समिट के दौरान हुई थी। इससे पहले वह जनवरी में वतौर गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट और उसके वाद जुन में इटली में त्र7 समिट के दौरान दोनों नेताओं के वीच मुलाकात हुई थी। इससे पहले एआई समिट 2024 में साउथ कोरिया में हुआ था।

डिफेंस डील होगी

फ्रांस सरकार ने कहा है कि ग्लोवल एआई सेक्टर के जरिए इस तरह के फैसले लिए जाएंगे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में सार्वजनिक महत्व की दिशा में आगे बढ़ा जा सकते। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और फ्रांस के वीच दो वड़ी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश पर अदालत ने लगाई रोक

एक फेडरल जज ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वत: जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। जज ने इस आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के आदेश पर कहा, जाहिर है कि हम अपील करेंगे ।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिएटल स्थित अमेरिकी जिला जज जॉन कफनौर ने चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों - वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन - की अपील पर एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया ।रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त जज ने इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन की कठोर नीतियों को पहला कानूनी झटका दिया। बता दें ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान अवैध प्रवासियों का मुद्दा बार-बार उठाया था ।न्यायाधीश ने ट्रम्प के आदेश का बचाव करने वाले अमेरिकी न्याय विभाग के वकील से कहा, मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का एक सदस्य स्पष्ट रूप से कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरे दिमाग को चकरा देता है। इससे पहले सोमवार को राष्टपति ने जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए इसे बिल्कुल हास्यास्पद% अवधारणा करार दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है, जिसके पास ऐसा नियम है ।कार्यकारी आदेश के मुताबिक अमेरिका में जन्मे बच्चे - [जिनके माता-पिता में से कम से कम एक नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं है] - को अब स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।

डॉलर के सामने रुपये में गिरावट पर कांग्रेस का तंज

नईदिल्ली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुद्रा में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसे शतक बनाने का मन बना लिया है। हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वह इसे लेकर आई हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं चल पाया है कि रुपया कितनी तेजी से गिर गया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की गरिमा भी।

मोदी पर तंज कसते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं आज अपने साथ मैग्निफाइंग ग्लास लेकर आई हूं, इसी से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है? इसी के साथ ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा कहां तक गिरी है? आज रुपया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, संभाले नहीं संभल रहा। रुपया 87 पर गोते लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी को कोई बताए कि रुपए से सेंचुरी नहीं लगवानी है.. रुपए को संभालना है।

अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था- जैसे-जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। सुना है प्रधानमंत्री आवास पर खुदाई चल रही है और ढूंढा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा आखिर कौन से गड्ढे में

जाकर गिर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर 87 पार लगाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब हमने उन्हें रुपया 58 पर दिया था। यानी उस समय एक डॉलर की कीमत 58 रुपए थी।

श्रीनेत ने कहा कि मई 2014 में 1 डॉलर: 58 रुपए और जनवरी 2025 में 1 डॉलर : 87 रुपए है। उन्होंने कहा कि अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया है। वे लगातार रुपए को पतला करते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने पूरी ताकत लगा दी है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन था, रुपए को बचाने के लिए उसमें से लगभग 80 बिलियन खर्च कर दिए गए। मतलब करीब 6,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन रुपया संभाले नहीं संभल रहा है।

कर्नाटक विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दे केंद्र : खरगे

बेंगलूरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने प्रधान से कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को जल्द से जल्द से मंजूरी देने का आग्रह किया। यहां खरगे जिन प्रस्तावों की बात कर रहें है वे अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है।

केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में खरगे ने कहा कि यह विश्वविद्यालय कर्नाटका और उसके आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लिखा कि ये विश्वविद्यालय शैक्षिक असमानताओं को दूर करने और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है।

साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने कुछ नए स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिए हैं, जैसे सांख्यिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पादप और पशु विज्ञान, आनुवंशिकी, और अन्य। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 55 नए शिक्षण पदों की भी आवश्यकता है ताकि इन विभागों को चालू किया जा सके। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सरकार से हरी झंडी की जरूरत है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री से इन प्रस्तावों की मंजूरी में तेजी लाने की अपील की है, ताकि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र और वंचित छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

दिल्ली के चुनावी दंगल में आज होगी अमित शाह की एंट्री

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरवरी की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार गतिविधियों के तहत शनिवार, 25 जनवरी को दिल्ली में सार्वजनिक सभाएं और रोड शो करेंगे। शाह के यात्रा कार्यक्रम में शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर दो सार्वजनिक सभाएं और एक रोड शो शामिल है। 5 फरवरी को 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी तो नतीजे आएंगे। भाजपा राजधानी में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उसके सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है।

बताया जा रहा है कि शनिवार को शाह की सार्वजनिक सभाएं राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली हैं, जबकि रोड शो आदर्श नगर इलाके में होगा। प्रारंभिक सार्वजनिक सभा दोपहर के समय राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित है, जहां शाह स्थानीय लोगों और पार्टी सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण मामलों और विकासात्मक योजनाओं के बारे में संवाद करेंगे। इसके बाद, मंत्री आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में केवल पार्क से रामलीला मैदान तक एक रोड शो में शामिल होंगे।

खेल

प्रमुख समाचार

आईसीसी वनडे टीम में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं

नईदिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को वर्ष 2024 की आईसीसी पुरुष वनडे टीम की घोषणा की है। एक भी भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण अफ्रीकी या इंग्लैंड खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया है। टीम में चार श्रीलंकाई, तीन पाकिस्तानी और दो अफगानी प्लेयर हैं। 2024 में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ तीन वनडे मैच खेले और तीनों मैच हार का सामना करना पड़ा। टीम के ओपनर पाकिस्तान के सईम अयूब और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज़ हैं।

जहां अयूब ने नौ मैच खेले और 64 की औसत से 515 रन बनाए, वहीं गुरबाज़ ने 11 मैचों में 531 रन बनाए हैं। श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। उन्होंने 12 मैचों में 106 की जबरदस्त औसत के साथ 694 रन बनाए। मध्य क्रम की जिम्मेदारी श्रीलंका के कप्तान चैरिथ असलांका को सौंपी गई। 17 मैचों में 742 रन बनाए हैं। वह टीम का नेतृत्व भी करेंगे। विकेटकीपर कुसल मेंडिस हैं, जिन्होंने पिछले साल 17 मैचों में 742 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज के शारफेन रदरफोर्ड भी टीम में फिनिशर के रूप में जगह बनाते हुए शामिल हुए हैं। उन्होंने नौ मैचों में 120 की स्ट्राइक रेट और 106 की शानदार औसत के साथ 429 रन बनाए हैं। पूरे साल 12 मैचों में 17 विकेट लिए। एक और श्रीलंकाई खिलाड़ी इस सूची में शामिल है, क्योंकि वानिंदु हसरनागा ने 10 मैचों में 7/19 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े के साथ 26 विकेट लिए हैं। टीम में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की पाकिस्तानी पेस जोड़ी भी है। अफरीदी ने जहां छह मैचों में 15 विकेट लिए, वहीं रऊफ ने आठ मैचों में 13 विकेट लिए। अफगान किशोर ऑफ स्पिनर अल्लाह गज़नफ़र 11 मैचों में 21 विकेट लेकर शामिल हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 330 अंक टूटा निफ्टी 23,092 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बावजूद घरेलू शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार (24 जनवरी) को गिरकर बंद हुए। देसी कंपनियों के दिसंबर तिमाही नतीजों को लेकर चिंता की वजह से दोनों प्रमुख इंडेक्स लगातार तीसरे हफ्ते साप्ताहिक गिरावट में बंद हुए। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे हैवीवेट शेयरों में मुनाफावसूली ने भी बाजार को नीचे की तरफ खींचा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसक्स आज मामूली गिरावट के साथ 76,455 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 76,985 अंक के हाईएस्ट और 76,091 अंक के नीचले स्तर तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 329.92 अंक या 0.43% की गिरावट लेकर 76,190.46 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी आज लाल और हरे निशान में झूलने के बाद 113.15 अंक या 0.49% गिरकर 23,092 पर बंद हुआ।

अगले शनिवार को पेश होगा आम बजट

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025, शनिवार को आम बजट पेश करेंगी। इस दिन भारतीय शेयर बाजारों में भी सामान्य रूप से कामकाज होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने सर्कुलर जारी कर बताया है कि 1 फरवरी को बाजार सामान्य समय पर खुले रहेंगे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहते हैं, लेकिन बजट के दिन बाजार में लाइव ट्रेडिंग होगी। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट भाषण देंगी। यह उनका आठवां बजट भाषण होगा, जिसमें छह वार्षिक बजट और दो अंतरिम बजट शामिल हैं। बजट भाषण का सीधा प्रसारण संसद टीवी और दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनलों पर किया जाएगा।

अदाणी को झटका, श्रीलंका ने पावर से जुड़ी डील की रद्द

नईदिल्ली। श्रीलंका ने अदाणी ग्रुप के साथ बिजली खरीद को लेकर किए गए समझौते को रद्द कर दिया है। यह कदम अदाणी पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उठाया गया है। इस खबर की पुष्टि शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएफपी ने की, जिसमें देश के ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला दिया गया। श्रीलंका के नए राष्टपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अदाणी के स्थानीय प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू की थी। यह कदम उस समय उठाया गया जब पिछले साल अदाणी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। मई 2024 में, पिछली सरकार ने अदाणी के एक पवन ऊर्जा संयंत्र से, जो अभी श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम में बनना बाकी है, बिलियन 0.0826 प्रति किलोवॉट की दर से बिजली खरीदने पर सहमति जताई थी। हालांकि, वर्तमान सरकार ने इस महीने की शुरुआत में यह फैसला किया कि वह इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगी।

अरविंद स्मार्टस्पेसेज का एमएमआर में बड़ा निवेश

नईदिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी अरविंद स्मार्टस्पेसेज लिमिटेड ने 92 एकड़ में टाउनशिप बनाने के लिए संयुक्त विकास समझौता किया है। इससे 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होने का अनुमान है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, उसने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में एक बड़ी क्षैतिज, बहुउपयोगी परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं‘ जिसका कुल अनुमानित क्षेत्रफल 92 एकड़ है और जिससे कुल 1,500 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।'' कंपनी ने मुंबई के खोपोली के पास स्थित इस टाउनशिप के निर्माण के लिए सच डेवलपर्स के साथ समझौता किया है। इस परियोजना के लिए संयुक्त विकास मॉडल (70.5 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी) के तहत समझौता किया गया है।

वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपए को गिरने से बचाने हेतु कम करना होगा आयात

प्रहलाद सबनानी

एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 86.62 रुपए तक के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, बहुत सम्भव है कि आगे आने वाले समय में यह 87 रुपए अथवा 90 रुपए के स्तर को भी पार कर जाय। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की गिरावट के लिए वैश्विक स्तर पर कई कारक जिम्मेदार है परंतु मुख्य रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगातार मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे, रोजगार हेतु नई नौकरियों की तो जैसे बहार ही आई हुई है। जनवरी 2025 माह में दिसम्बर 2024 माह के जारी किए के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 256,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा हुई हैं जबकि अनुमान लगभग 200,000 नौकरियों का ही था, नवम्बर 2024 माह में 212,000 नौकरियां पैदा हो सकी थीं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के चलते फेडरल रिजर्व, यूएस फेड रेट में कमी की घोषणा को रोक सकता है एवं अब अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का मत है कि केलेंडर वर्ष 2025 में केवल एक अथवा दो बार ही फेड रेट में कमी की घोषणा हो, क्योंकि, रोजगार के क्षेत्र में मजबूती के चलते बहुत सम्भव है कि मुद्रा स्फीति में कमी लाने में अधिक समय लग सकता है। अमेरिका में बढ़ी हुई ब्याज दर के चलते अमेरिकी डॉलर इंडेक्स एवं अमेरिकी ट्रेजरी बिल पर यील्ड भी मजबूत बनी हुई है इससे अमेरिकी डॉलर लगातार और अधिक मजबूत हो रहा है एवं पूरे विश्व से डॉलर अमेरिका की ओर आकर्षित हो रहा है जबकि इसके विरुद्ध अन्य देशों की मुद्राओं पर स्पष्टत- दबाव दिखाई दे रहा है।

दिनांक 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के राष्टपति पद की शपथ

लेने के बाद बहुत सम्भव है कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले कई उत्पादों पर आयात कर की दर बढ़ा दी जाय क्योंकि अमेरिकी राष्टपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान बार बार इसका जिक्र किया गया है। यदि ऐसे निर्णय अमेरिका में लागू किए जाते हैं तो इससे अमेरिका में मुद्रा स्फीति फैलेगी और यदि ऐसा होता दिखाई देता है तो यू एस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी के स्थान पर वृद्धि की घोषणा भी कर सकता है। इससे अमेरिकी डॉलर में और अधिक मजबूती आएगी और अन्य देशों की मुद्राओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अवमूल्यन होने लगेगा।

दूसरे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें भी एक बार पुन: बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो 81 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं। इससे भी भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत आज भी अपने कच्चे तेल की कुल खपत का 87 प्रतिशत से अधिक तेल का आयात करता है और इस आयातित कच्चे तेल का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होता है, जिससे भारत के लिए अमेरिकी डॉलर की मांग भी लगातार बढ़ रही है। बल्कि इससे तो भारत में भी मुद्रा स्फीति के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। पिछले वर्ष भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 13,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च की है।

तीसरे, विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका में ब्याज दरों के अच्छे स्तर को देखते हुए अपने निवेश पर अधिक आय की सम्भावना दिखाई दे रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा 27 सितम्बर 2024 से भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली की जा रही है और दिनांक 17 जनवरी 2025 तक 232,317 करोड़ रुपए की बिकवाली शेयर बाजार में उनके द्वारा की जा चुकी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक देश की मुद्रा की तुलना में दूसरे देश की मुद्रा की कीमत यदि गिरने लगे तो इसके पीछे सामान्यत: दोनों देशों में मुद्रा स्फीति की दर को जिम्मेदार माना जाता है। जैसे यदि अमेरिका में मुद्रा स्फीति की दर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और भारत में मुद्रा स्फीति की दर 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है तो भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2.5 प्रतिशत से गिरनी चाहिए।

क्रमशः ...

छत्तीसगढ़ के विकास से कांग्रेस दुखी और बुरी तरह निराश :केदारनाथ

पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने खुद की कुर्सी बचाने छत्तीसगढ़ का पैसा गांधी परिवार के पास इन्वेस्ट किया विष्णुदेव साय सरकार में पूरे भारत के लोग छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं केदारनाथ गुप्ता

नक्सली मारे जा रहे है ,लाखों करोड़ों का निवेश आ रहा है,रोजगार मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ में विकास का नया सूरज निकला हैः केदारनाथ गुप्ता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने प्रेस ब्रीफ को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाल ही के दिनों में मुंबई में छत्तीसगढ़ %इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट% का दूसरा चरण आयोजित किया गया। छत्तसीगढ़ को भारत के मुख्य मार्ग पर प्रशस्त करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाये है। यह इन्वेस्टर्स समिट उनमे से एक है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को प्लास्टिक, कपड़ा, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों से 6,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमेरिकी महावाणिज्य दूत माइक हैंकी और रूस के महावाणिज्य दूत इवान वाई फेटिसोव के साथ राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का मूलतंत्र %न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के आदर्श को दुनिया के सामने रख छत्तीसगढ़ को वाणिज्य और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदर्शित किया। राज्य की नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ को रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन बैठकों के माध्यम से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

पिछले साल दिसम्बर 2024 में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में प्रदेश को 15,184 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। इसमें प्रमुख रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने इनमें से 75त्न प्रस्तावों पर प्रतिबद्धता जताई थी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने हेतु भाजपा की सरकार ने कई नवीनतम कदम उठाए है। जंहा कांग्रेस केवल राज्य और भारत को दशकों पहले के जंजाल में धकेलना चाहती है, वही यह भाजपा ही है जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए और साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए साय सरकार के कई कदम उठाए है, जैसे ङ्क

अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, और अब मंजूरी एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दी जाती है, जिससे निवेशकों को काफी राहत मिली है।

नया रायपुर में एक नए डेटा सेंटर के शुभारंभ की घोषणा, जिससे शहर को सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करने में और मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष रियायतें हैं।

गुप्ता ने कहा इसके अतिरिक्त, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार और ईपीएफ प्रतिपूर्ति के साथ-साथ 5 से 12 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं।% बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ-साथ लौह और कोयला रॉयल्टी पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट शुरू की गई है। निवेश और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ के निवेश वाले या 1,000 लोगों को रोज़गार देने वाले उद्योग बेस्पोक पॉलिसी के लिए पात्र है। इस पॉलिसी में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश के प्रावधान शामिल हैं, जिनकी राशि 200 करोड़ से 450 करोड़ के बीच है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में निवेश लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उनकी घोषणाओं और वादों की पोल खुल गई जब उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा किया, जो आखिरकार पूरा नहीं हुआ। वो सरकार बस लोगों को बहलाने और झूठे वादों से गुमराह करने में लगी रही, जबकि राज्य के विकास के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ। हमारी सरकार का यह पहल पूरी तरह से प्रगतिशील है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ युवाओं की उम्मीदों को भी पूरा करेगी। पिछले बघेल सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं को कुचला था, लेकिन हमारी योजना में राज्य के विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। हम न केवल युवाओं के भविष्य को संवारेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे, जो बघेल सरकार के समय में लगातार कमजोर होती गई।

कांग्रेस हमेशा चाहती है कि जनता गरीब बनी रहे ताकि उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे। वह ग़रीबी हटाओ का नारा पचास वर्ष तक चलाती रही। वह उद्योग-धंधों के खिलाफ और नक्सलियों के पक्ष में है, इसलिए यह चिंता जता रही है कि नक्सल समाप्त होने पर उद्योग धंधे आयेंगे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि लगातार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। 250 से अधिक नक्सली मारे गये हैं। अधिकतर की सूची जारी की है नक्सलियों ने, दो हज़ार से अधिक नक्सली गिरफ्तार/आत्मसमर्पित हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल इसे फर्जी बताते हैं, महंत को चिंता है कि उद्योग आ जाएगा इससे, यह निंदनीय है। आपने देखा कि स्व सहायता समूह की 22 हजार से अधिक महिलाओं का छीन कर सड़क पर ला दिया था कांग्रेस ने। अब उसकी भी बहाली कर रहे हैं हम। छः ज़िलों में यह शुरू भी हो गया है। अन्य में भी जल्दी होगा। कांग्रेस द्वारा उजाड़े गये 22 हजार परिवार भी बसेंगे, बच्चों को फिर से गर्म भोजन भी मिलेगा। कांग्रेस ने कमीशन के चक्कर में तबाह कर दिया था।

प्रेस ब्रीफ में प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी एवं भाजपा पैनिलस्ट सुनील चौधरी मौजूद रहे ।

पिछले साल के धान खरीदी का टूटा रिकार्ड

धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार

25 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान, अभी तक 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतान

कुल खरीदी का 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी

87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का हो चुका है उठाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष

आज दिनांक तक हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 24 जनवरी को 30 हजार 762 किसानों से 1.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 58 हजार 997 टोकन जारी किए गए थे।

शहर विकास को समर्पित होगा भाजपा का घोषणा पत्रः अमर

भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नगरीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा समिति के संयोजक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सह संयोजक-विधायक सुनील सोनी उपस्थित थे।

बैठक में घोषणा पत्र समिति के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और समिति के सदस्यों से सुझाव लिए गये। समिति के संयोजक पूर्व मंत्री व विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि नगर निगमों के समग्र विकास के हमारा घोषणा पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। हमारी जीत नगरीय निकाय चुनाव में विशाल होगी। जिसे ध्यान में रखते हुए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, जो शहरों के विकास के स्वरूप को समर्पित होगा। बैठक में पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, चन्द्रशेखर साहू, विधायक नीलकंठ टेकाम, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, प्रवक्ता दीपक म्हस्के, शशांक शर्मा, पूर्व महापौर सफीरा साहू, अंबिका यदु, उज्जवल दीपक, हेमंत पाणिग्रही शामिल थे।

आईजी ने बुलाई रेंज बैठक

चुनाव के दौरान शांति भंग करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई

रायपुर। प्रदेश में अगले माह फरवरी में निकाय चुनाव होना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। चुनाव के दौरान किसी तरह की शांति भंग न हो इसके लिए पुलिस ने भी तैयारिया शुरू कर दी है। होने वाले चुनाव को देखते हुये रायपुर रेंज आईजी अमरेंश मिश्रा ने संभाग के सभी एसपी, एएसपी, सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी की बैठक ली।

प्रथम पाली में रायपुर जिले के एसएसपी, एएसपी व राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राजधानी पुलिस की चुनौतियों से निपटने हेतु अधिकारियों को आवश्यक

दिशा निर्देश दिये गये। राजपत्रित अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने, कार्यक्षमता में वृद्धि कर गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण करने, प्रत्येक घटना की समीक्षा कर अधीनस्थ अधि0/कर्मचारियों को औचित्यपूर्ण निर्देश देने, थानों के कार्यों के मात्र पर्यवेक्षण तक सीमित न होकर कार्य में गुणवत्ता सुधार करने के निर्देश दिये गये।द्वितीय पाली की बैठक में रायपुर रेज के सभी एसपी, एएसपी व अन्य राजपत्रित अधिकारी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा सरकार के कुशासन से जनता परेशान : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। भाजपा सरकार के कुशासन से जनता परेशान है। राज्य में कानून

व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। राजधानी में 5 बार गोलीबारी हो गयी। गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गयी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 1 साल में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है। भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है।

भाजपा सरकार कर्ज लेकर घी पी रही हैः धनंजय ठाकुर

रायपुर। भाजपा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश कर्ज की दलदल में फंसते जा रही है। हर माह 3500 करोड रुपए का कर्ज ले रही है जिस

गति से कर्ज लिया जा रहा है आने वाले 5 साल में प्रदेश के ऊपर ढाई लाख करोड़ से अधिक का कर्ज होगा और इतना कर्ज लेने के बाद प्रदेश भी सरकार किसानों को धान की कीमत एक मुश्त 3100रु एवं धान बेचने बारदाना नहीं दे पा रही है। स्कूलों में शिक्षकों एवं सरकारी अस्पतालों में दवाइयां चिकित्सा सुविधा का अभाव है। आम जनता मूलभूत की सुविधाओं के लिए तरस रही है। सरकार के 13 महीने के कार्यकाल में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, राइस मिलर स्टील निर्माता, उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर, शासकीय कर्मचारी हर वर्ग आंदोलन कर चुके ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार के काम से खुश होगा।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने दावा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश को आर्थिक मदद करेगी 13 महीने में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को फूटी कौड़ी नहीं दिया है बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता ने केंद्र सरकार को जीएसटी के रूप में करोड़ों रुपए दिया है।

साय सरकार ने 1 साल में रोजगार छीनाः शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार 1 साल में एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पायी है, बल्कि युवाओं से रोजगार छीनने का ही काम किया है। कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी दर मात्र 0.60

प्रतिशत था। भाजपा सरकार बनने के बाद बेरोजगारों की संख्या में भारी वृद्धि हुआ है। 1 साल में बीएड शिक्षक, अतिथि शिक्षक, विद्या मितान, क्रेडा के संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, वन विभाग के संविदा कर्मचारियों, गोठान महिला स्व सहायता समूह, रीवा के तहत रोजगार प्राप्त कर रहे लोगों को काम से बेदखल किया गया, ई-श्रेणी के लाइसेंस में काम कर रहे युवाओं से भी काम छिन गया है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप है कोई नई भर्ती पूरी नहीं हुई है पूर्व से चल रही भर्ती में भी नियुक्तियां नहीं दी जा रही है हर विभाग में काम करने वाले युवाओं से उनका हक अधिकार को छीना गया है। ऐसे में साय सरकार का रोजगार देने का दावा सरासर जुमला और मनगढ़ंत आंकड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 1 साल में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती का अवसर दिया गया है कितने मजदूरों को काम दिया गया है।

सरकार की नीतियां स्थानीय उद्योगों के खिलाफ़ हैः वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पिछले 13 महीने की सरकार के दौरान उद्योग के अनुकूल माहौल दे पाने में भाजपा सरकार पूरी तरह

नाकाम साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार आने के बाद से 1 वर्ष के भीतर ही चार-चार बार बिजली के दाम बढ़े हैं। स्टील उद्योग को छत्तीसगढ़ की रीढ़ कहा जाता है, हमारे प्रतिस्पर्धी राज्य उड़ीसा और झारखंड है जहां पर कम कीमत में बिजली मिल रही है। जमीन हमारी, कोयला हमारा, पानी हमारा और हमारे ही लोगों को दो से तीन रुपया प्रति यूनिट अधिक दाम पर बिजली यह कहां का न्याय है? सरकार की गलत नीतियों के चलते विगत 1 वर्ष के भीतर 180 से अधिक मैं स्टील प्लांट और रोलिंग मिल बंद हुए हैं। जिसके चलते 12 एथेनॉल प्लांट लगे, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बने, कोदो, कुटकी रागी की प्रोसेसिंग शुरू हुई, 2018 से 2023 के बीच प्रदेश में 700 से अधिक नए राइस मिल बने लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उद्योगों पर संकट गहरा गया जिसके चलते विगत एक वर्ष में 300 से ज्यादा राइस मिलें बंद हो गई।

24 फरवरी से बजट सत्र 21 मार्च तक होंगी 17 बैठकें

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। साय सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका के भाषण से होगी।इस दौरान सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लेकर आएगी। अगले दिनों से उस पर चर्चा होनी है। इस सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सत्र में मोदी की गारंटी को लेकर बड़ी योजनाएं आ सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला बजट 9 फरवरी साल 2025 में पेश किया था। प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का ये बजट पेश किया था, जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22 फीसदी ज्यादा थी।वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट %ज्ञान% यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड बताया था। वित्त मंत्री चौधरी ने अपने बजट के दौरान कहा था कि, त्र्ङ्खन्न् के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 साल में त्रष्ठक्क को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं।

एनआईटी में नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर ने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल के सहयोग से 24 जनवरी, 2025 को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन आउटकम बेस्ड एजुकेशन विषय पर आधारित कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया 7 22 से 24 जनवरी तक आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों के बीच परिणाम-आधारित शिक्षा प्रैक्टिसेस की समझ और कार्यान्वयन को बढावा देना था। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डीन (अकादमिक) डॉ. श्रीश वर्मा, संरक्षक के रूप में डीन (एफ

डब्ल्यू) डॉ. देबाशीष सान्याल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. शुभाशीष सान्याल भी शामिल हुए। एनआईटीटीटीआर, भोपाल के डॉ. बद्रीलाल गुप्ता और डॉ. हुसैन जीवाखान ने विशेष अतिथि और एक्सपर्ट लेक्चर के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में डॉ. लता एस. बी. उपाध्याय और डॉ. मृदु साहू एसोसिएट डीन (एफडब्ल्यू) भी उपस्थित रही।

यह कार्यक्रम डीन फैकल्टी वेलफेयर ऑफिस द्वारा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों के विकास के लिए आयोजित की गई । इस तीन दिवसीय कार्यशाला में एनईपी 2020 और एनबीए दिशानिर्देशों पर आधारित चर्चाएँ की गई। इस दौरान एनआईटीटीटीआर के विशेषज्ञों ने ई-परिक्षण- अ आउटकम बेस्ड लर्निंग प्लेटफार्म के बारे में भी जानकारी दी।

डॉ. एस. सान्याल ने कार्यशाला के आयोजन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रभावी शिक्षण सीखने और मूल्यांकन प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डाला, जो तीन दिवसीय यात्रा का मुख्य हिस्सा थे। एनआईटीटीटीआर सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सराहना करते हुए उन्होंने विशेषज्ञों के लिए आभार व्यक्त किया। डॉ. डी. सान्याल ने व्यावहारिक अनुभव साझा किए और शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान किया 7 उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखने और संगठित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. वर्मा ने पिछले चार वर्षों में शैक्षणिक प्रथाओं में परिवर्तनकारी बदलावों पर प्रकाश डाला, तथा सीखने और नवाचार को प्रेरित करने के लिए परिणाम-आधारित शिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने आपसी जुड़ाव बढ़ाने के लिए चैटबॉट इंटरैक्शन जैसे अभिनव तरीकों पर चर्चा की और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की वकालत की।

मार्च-पास्ट, पदक अलंकरण सहित हुई फुल ड्रेस फायनल रिहर्सल

रायपुर। राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा। राज्यपाल रमेन डेका मुख्य समारोह स्थल में ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज सुबह पुलिस परेड ग्राउण्ड में फूल डेऊस फायनल रिहर्सल हुई। इस अवसर पर डीजीपी अशोक जुनेजा, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।इस बार 17 सुरक्षा बल की टुकड़ी परेड में शामिल होंगी। इसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, तेलंगाना पुलिस, नगर सेना पुलिस एवं महिला, एनसीसी गर्ल्स एवं बॉयज, घुड़सवार बल, बैंण्ड प्लाटून पुलिस और महिला बैग पाईपर बैंड दस्ता शामिल हैं।

तेलंगाना पुलिस का प्लाटून विशेष रूप से शामिल हैं। सम्पूर्ण परेड आयोजन के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा हैं। इसके सहायतार्थ उप पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविन्द कुजूर (आई.पी.एस.) एवं सेनानी प्रफुल्ल ठाकुर (आई.पी.एस.) होंगे। रिहर्सल में आकर्षक मार्च-पास्ट के साथ पदक अलंकरण समारोह और अन्य कार्यक्रमों की पूर्व तैयारियों को परखा गया। राज्यपाल के सुरक्षा अधिकारी डीएसपी गिरीश कोरी रिहर्सल में राज्यपाल की भूमिका निभाकर तैयारियों का जायजा लिया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.